नवसर्जन संस्कृति

RNI No. GJHIN/25/A2786
NAVSARJAN SANSKRUTI

नवसर्जन संस्कृति

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 183
दि. 07.04.2026,
मंगलवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

मध्यस्थों का 45 दिन का युद्धविराम प्रस्ताव: ईरान और अमेरिका के बीच तनाव घटाने की कोशिश

काहिरा। ईरान और अमेरिका के बीच जारी तनाव को खत्म करने के प्रयास में मध्यस्थ देशों ने एक विशेष प्रस्ताव तैयार किया है, जिसमें दोनों पक्षों के लिए 45 दिन का युद्धविराम और होर्मुज जलडमरूमध्य को समुद्री यातायात के लिए फिर से खोलने की मांग शामिल है। सूत्रों के अनुसार, यह प्रस्ताव रविवार देर रात अमेरिका और ईरान को भेजा गया और इसे ईरानी पावर प्लांट और अन्य बुनियादी ढांचों पर होने वाले बड़े हमलों को रोकने की आखिरी कोशिश माना जा रहा है।

मध्यस्थों ने दोनों पक्षों के बीच बातचीत के लिए पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र को भी शामिल किया है। इन देशों का जोर इस बात पर है कि युद्धविराम के दौरान दोनों देशों को शांति वार्ता के लिए पर्याप्त समय दिया जाए ताकि स्थायी समाधान निकाला जा सके। प्रस्ताव के तहत पहला चरण 45 दिन का संभावित युद्धविराम होगा, जबकि दूसरे चरण में युद्ध को स्थायी रूप से समाप्त करने के लिए समझौते की दिशा में चर्चा होगी। यदि आवश्यक हुआ तो मध्यस्थ सीजफायर की अवधि बढ़ाने की भी संभावना रख रहे हैं।

पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी ने बताया कि उनकी सरकार संघर्षविराम कराने की दिशा में लगातार प्रयास कर रही है और वार्ता की प्रक्रिया सही दिशा में आगे बढ़ रही है। इसी तरह तुर्की और मिस्र भी अमेरिका और ईरान को बातचीत की मेज पर लाने के प्रयास में जुटे हुए हैं। ये मध्यस्थ केवल युद्धविराम तक सीमित नहीं रहना चाहते, बल्कि स्थायी शांति और विश्वास बहाली के उपायों पर भी काम कर रहे हैं।

ईरान ने इस प्रस्ताव पर अपनी शर्तें रखी हैं। सूत्रों के अनुसार, होर्मुज जलडमरूमध्य को पूरी तरह से खोलने और ईरान के पास अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम जैसे मुद्दों को केवल अंतिम समझौते के हिस्से के रूप में ही सुलझाया जा सकता है। इसके साथ ही ईरान ने युद्ध का हर्जाना, सुरक्षा गारंटी और अमेरिकी

विश्वास बहाली के उपायों को भी अपनी शर्तों में शामिल किया है। ईरान के संस्कृति मंत्री सैयद रजा सालिही-अमीरी ने अमेरिकी धमकियों को खारिज करते हुए कहा कि ट्रंप के बयान अक्सर अस्थिर और विरोधाभासी होते हैं और ईरानी समाज ऐसे बयानों को गंभीरता से नहीं लेता।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को ईरान को चेतावनी देते हुए कहा कि सोमवार तक समझौते की प्रबल संभावना है, लेकिन यदि ईरान वार्ता में तेजी नहीं दिखाता है तो अमेरिका और कड़ा कदम उठा सकता है। ट्रंप ने फॉक्स न्यूज से बातचीत में कहा कि यदि ईरान समझौते की दिशा में तेजी नहीं दिखाता है तो अमेरिका युद्ध के विकल्पों पर विचार कर रहा है, जिसमें ऊर्जा संसाधनों और तेल पर नियंत्रण भी शामिल हो सकता है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में चेतावनी दी थी कि यदि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खोला नहीं गया तो ईरान के ऊर्जा संयंत्रों और पुलों पर हमले किए जा सकते हैं।

मध्यस्थों का लक्ष्य है कि 45 दिन के सीजफायर के दौरान दोनों पक्ष विश्वास बहाली के उपायों पर सहमति बनाएं और स्थायी शांति की दिशा में कदम उठाएं। प्रस्ताव को लेकर कूटनीतिक गलियारों में इसे अंतिम मौका माना जा रहा है। यदि यह सफल होता है तो यह केवल युद्धविराम तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि दोनों देशों के बीच स्थायी शांति समझौते की राह भी प्रशस्त करेगा। सूत्रों के अनुसार, युद्धविराम और शांति प्रक्रिया के लिए पाकिस्तान ने वार्ता की मेज पर दोनों पक्षों को लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पाकिस्तान के अलावा तुर्की और मिस्र भी बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। इस प्रस्ताव के तहत 45 दिन का युद्धविराम एक ऐसा समय अंतराल प्रदान करेगा, जिसमें सभी विवादों और शर्तों पर चर्चा की जा सकेगी और लंबी बातचीत के बाद स्थायी समाधान निकाला जाएगा।

हालांकि, ट्रंप ने अभी तक इस प्रस्ताव पर दस्तखत नहीं किए हैं और उनके रुख के कारण ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बरकरार है। मध्यस्थ देशों की कोशिश है कि वे दोनों पक्षों को बातचीत के लिए मजबूर करें और युद्ध की विभीषिका को रोकें। उन्होंने उम्मीद जताई है कि 45 दिनों की अवधि के दौरान दोनों देशों के बीच विश्वास बहाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएंगे।

ईरान की प्रतिक्रिया भी स्पष्ट रही है। संस्कृति मंत्री सालिही-अमीरी ने कहा कि होर्मुज जलडमरूमध्य 'दुनिया के लिए खुला है, लेकिन ईरान के दुश्मनों के लिए बंद है'। उन्होंने स्पष्ट किया कि ईरान किसी भी अंतिम समझौते के लिए अपनी सुरक्षा और अधिकारों पर कोई समझौता नहीं करेगा। उनका कहना है कि अमेरिका के व्यवहार में लगातार विरोधाभास हैं और दोनों देशों के बीच संतुलित वार्ता के लिए मध्यस्थ देशों की भूमिका निर्णायक होगी। इस पूरे परिदृश्य में मध्यस्थ देशों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हो रही है। पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र न केवल युद्धविराम की पहल कर रहे हैं, बल्कि वे दोनों पक्षों को विश्वास बहाली, शांति वार्ता और स्थायी समझौते की दिशा में मार्गदर्शन भी प्रदान कर रहे हैं। कूटनीतिक जानकार मानते हैं कि यदि 45 दिन का प्रस्ताव सफल हुआ, तो यह क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता के लिए एक नया मील का पत्थर साबित हो सकता है।

कूटनीतिक विश्लेषक यह मान रहे हैं कि होर्मुज जलडमरूमध्य का खुलना वैश्विक तेल बाजार और अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसके खुलने से ना केवल ऊर्जा आपूर्ति में स्थिरता आएगी, बल्कि क्षेत्रीय तनाव को कम करने में भी मदद मिलेगी। वहीं, युद्धविराम की अवधि के दौरान दोनों देशों को किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई से रोकने के लिए मध्यस्थ पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसलिए 45 दिन के युद्धविराम प्रस्ताव को केवल सैन्य संघर्ष रोकने का उपाय नहीं, बल्कि यह विश्वास बहाली, स्थायी शांति और क्षेत्रीय स्थिरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। यदि दोनों पक्ष इस अवसर का सही उपयोग करते हैं, तो यह प्रस्ताव केवल अस्थायी शांति तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ईरान और अमेरिका के बीच स्थायी समझौते की नींव भी रख सकता है। कुल मिलाकर, मध्यस्थ देशों द्वारा तैयार किया गया यह प्रस्ताव न केवल क्षेत्रीय राजनीति के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था और समुद्री व्यापार के लिए भी निर्णायक साबित हो सकता है।

दिल्ली विश्वविद्यालय के रामजस और मिरांडा कॉलेज में बम धमकी से हड़कंप, पूरे परिसर में तलाशी जारी

नई दिल्ली। सोमवार को दिल्ली विश्वविद्यालय के दो प्रमुख कॉलेज, रामजस कॉलेज और मिरांडा हाउस कॉलेज, को बम धमकी मिलने से पूरे परिसर में हड़कंप मच गया। पुलिस और कॉलेज प्रशासन ने तुरंत कदम उठाते हुए छात्रों और स्टाफ को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया और परिसर को खाली कराया। धमकी भरे ईमेल के बाद बम निरोधक दस्ते (Bomb Disposal Squad) और डॉग स्क्वॉयड को बुलाकर पूरे कॉलेज परिसर की तलाशी ली गई।

पुलिस के अनुसार, कॉलेज के प्रधानाचार्यों को भेजे गए ईमेल में स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि परिसर में कुल 13 बम लगाए गए हैं और ये दोपहर तक विस्फोटित हो सकते हैं। धमकी में यह भी कहा गया कि केवल मुस्लिम छात्रों को ही कॉलेज परिसर से बाहर निकाला जाए। पुलिस ने बताया कि ईमेल में अत्यधिक आपत्तिजनक और सांप्रदायिक भाषा का प्रयोग किया गया है, जिससे कट्टरता और खतरे की गंभीरता का पता चलता है। धमकी वाले ईमेल में 'ऑर्डर ऑफ 9 एंगल (O9A)' नामक एक संदिग्ध संगठन का भी उल्लेख किया गया है। इस धमकी के बाद कॉलेज प्रशासन ने सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए सभी छात्रों और शिक्षकों को परिसर से

बाहर निकालकर नजदीकी सुरक्षित स्थानों पर ले जाया। पुलिस अधिकारियों ने परिसर की हर इमारत, कक्ष और परिसर के बाहर के आसपास के इलाके की भी पूरी जांच की। बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वॉयड ने परिसर की तलाशी पूरी की और किसी संदिग्ध वस्तु की खोज में विशेष निगरानी रखी। दिल्ली में हाल ही में सुरक्षा संबंधी मामलों को लेकर सतर्कता बढ़ाई गई है। इससे पहले भी कुछ हफ्ते पहले दिल्ली विधानसभा सचिवालय और विधानसभा स्पीकर के ईमेल पते पर धमकी भरे ईमेल आए थे, जिनमें संभावित धमाकों का उल्लेख किया गया था। वह ईमेल कथित तौर पर खालिस्तानी संगठन की ओर से भेजे जाने की बात कही गई थी। पुलिस ने उस मामले में अब तक कोई सार्वजनिक खुलासा नहीं किया है।

सोमवार को आए ईमेल में सिर्फ दिल्ली के कॉलेजों का ही नहीं, बल्कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और उनके परिवार को निशाना बनाने की भी बात की गई। इससे यह स्पष्ट होता है कि धमकी देने वालों ने राजनीतिक और सांप्रदायिक दोनों ही उद्देश्यों को ध्यान में रखकर यह ईमेल भेजा है। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी संभावित साजिशों और संदिग्ध गतिविधियों की जांच की जा रही है। दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों और शिक्षकों को सुरक्षा के लिए निर्देश जारी किए हैं और परिसर में आने-जाने पर विशेष सतर्कता बरतने को कहा गया है।

इस घटना ने दिल्ली विश्वविद्यालय में सुरक्षा व्यवस्था और साइबर सुरक्षा के महत्व को फिर से उजागर कर दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि ईमेल के जरिए दी जाने वाली धमकियों की पहचान करना और उन पर तुरंत प्रतिक्रिया देना आवश्यक है ताकि छात्रों और शिक्षकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

अब तक की जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि धमकी ईमेल में उल्लेखित संगठन और राजनीतिक लक्षित संदेश केवल भय उत्पन्न करने के लिए भेजे गए हो सकते हैं। हालांकि, पुलिस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है और डिजिटल फॉरेंसिक टीम को भी सक्रिय किया गया है। आने वाले दिनों में यह पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि धमकी ईमेल कहां से भेजे गए और इसके पीछे कौन लोग शामिल हैं।

इस मामले ने न केवल विश्वविद्यालय प्रशासन और पुलिस को सतर्क किया है, बल्कि छात्रों और अभिभावकों में भी सुरक्षा को लेकर चिंता पैदा कर दी है। अधिकारियों ने कहा है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि या वस्तु को तुरंत सुरक्षा एजेंसियों को सूचित किया जाए।

कुल मिलाकर, रामजस और मिरांडा कॉलेज में सोमवार को मिली बम धमकी ने पूरे विश्वविद्यालय परिसर में सुरक्षा अलर्ट जारी कर दिया है। पुलिस, बम निरोधक दस्ते और कॉलेज प्रशासन मिलकर जांच और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। छात्रों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है और मामले की जांच जारी है, जिससे आने वाले समय में कोई भी खतरा टाला जा सके।

अरविंद केजरीवाल दिल्ली हाई कोर्ट में पेश, खुद करेंगे पैरवी, न्यायमूर्ति शर्मा को हटाने की याचिका पर नोटिस जारी

नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट में सोमवार को शराब नीति मामले की सुनवाई के दौरान आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद पेश हुए और उन्होंने न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा को मामले से हटाने की याचिका दायर की। अदालत ने इस याचिका पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को नोटिस जारी किया है और अब मामले की अगली सुनवाई 13 अप्रैल को होगी।

इस मामले में सीबीआई ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी है, जिसमें दिल्ली सरकार की शराब नीति के तहत अरविंद केजरीवाल और अन्य 22 आरोपियों को बरी कर दिया गया था। निचली अदालत ने इस मामले में सीबीआई अधिकारी को फटकार लगाई थी, जिससे नाराज होकर केंद्रीय जांच एजेंसी ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। इस सुनवाई के दौरान केजरीवाल ने न्यायमूर्ति शर्मा को हटाने की याचिका दायर की, जिसका कारण उन्होंने अदालत में स्पष्ट किया।

केजरीवाल ने अदालत को बताया कि वे स्वयं अपना प्रतिनिधित्व करेंगे और अपनी याचिका की पैरवी खुद करेंगे। उन्होंने कहा कि स्व-पहचान संबंधी याचिकाकर्ताओं के लिए ई-फाइलिंग की सुविधा नहीं है, इसलिए

उन्होंने याचिका की हार्ड कॉपी अदालत में जमा की है। पीठ ने उनसे पूछा कि क्या आप स्वयं अपना पक्ष रखेंगे, जिस पर केजरीवाल ने स्पष्ट रूप से कहा कि मैं अपने कानूनी अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए खुद पैरवी करूंगा और अभी तक मैंने किसी को अपना वकालतनामा नहीं दिया है।

इस पर सीबीआई की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केजरीवाल की याचिका पर आपत्ति जताई। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि आवेदन खारिज हुआ, तो अदालत की अवमानना की कार्रवाई की जा सकती है। कोर्ट ने सीबीआई को आदेश दिया कि वे केजरीवाल की याचिका पर अपना जवाब दाखिल करें, जिसमें उन्होंने आबकारी नीति मामले में न्यायमूर्ति शर्मा को हटाने की मांग की है।

केजरीवाल ने न्यायमूर्ति शर्मा को हटाने की याचिका दायर करने का कारण भी स्पष्ट किया। निचली अदालत ने 27 फरवरी को शराब नीति मामले में केजरीवाल और अन्य आरोपियों को बरी कर दिया था, लेकिन सीबीआई ने इसे चुनौती दी। न्यायमूर्ति शर्मा ने 9 मार्च को निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाते हुए सीबीआई अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई पर रोक लगाई थी। इसके बाद केजरीवाल ने उच्च न्यायालय में उन्हें हटाने की याचिका दाखिल की।

विशेषज्ञों का मानना है कि केजरीवाल द्वारा स्वयं पैरवी करने का फैसला राजनीतिक और कानूनी दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यह कदम उनके अधिकार और अदालत में प्रत्यक्ष भागीदारी की स्पष्ट पहचान देता है। इसके अलावा, यह मामला दिल्ली सरकार की शराब नीति, सीबीआई की जांच प्रक्रिया और उच्च न्यायालय की भूमिका को लेकर गहन कानूनी बहस का केंद्र बना हुआ है।

कोर्ट ने इस याचिका पर 13 अप्रैल को सुनवाई तय की है। इस सुनवाई में यह स्पष्ट होगा कि न्यायमूर्ति शर्मा को मामले से हटाया जाएगा या नहीं और इसके साथ ही सीबीआई की चुनौती पर भी फैसला आएगा। यह मामला न केवल दिल्ली के राजनीतिक परिदृश्य में, बल्कि पूरे देश के न्यायिक इतिहास में भी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।

कुल मिलाकर, शराब नीति मामले की सुनवाई और केजरीवाल की याचिका ने न्यायिक प्रक्रिया और राजनीतिक नेतृत्व के बीच संबंध को एक बार फिर उजागर किया है। इस मामले में हाई कोर्ट के फैसले से भविष्य में सरकारी नीतियों और जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर असर पड़ सकता है, जबकि केजरीवाल की व्यक्तिगत पैरवी उन्हें कानूनी और राजनीतिक रूप से मजबूत स्थिति प्रदान कर सकती है।

पश्चिम बंगाल मतदाता सूची विवाद: नंदलाल बोस के परिवार का नाम गायब, विपक्ष ने चुनाव आयोग को घेरा

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले मतदाता सूची संशोधन अभियान (SIR) एक नए विवाद में फंस गया है। इस बार मामला बेहद संवेदनशील है क्योंकि भारतीय संविधान की मूल प्रति को अपने चित्रों से सजाने वाले महान कलाकार नंदलाल बोस के परिवार का नाम मतदाता सूची से गायब पाया गया। नंदलाल बोस, जिन्होंने मोहनजोदड़ो से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक के ऐतिहासिक चित्र बनाकर संविधान को भारतीय रंग में सजाया, उनके पोते सुप्रबुद्ध सेन और उनकी पत्नी का नाम इस सूची से अचानक हटा दिया गया।

सुप्रबुद्ध सेन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि शुरुआत में उनका नाम 'पेंडिंग' दिखाया गया और बाद में बिना किसी स्पष्ट कारण के उसे पूरी तरह हटा दिया गया। उनका कहना है कि यह मामला केवल व्यक्तिगत त्रुटि नहीं बल्कि निर्वाचन प्रक्रिया में गड़बड़ी का संकेत है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सूची से नाम हटाए जाने के बाद शिकायत करने पर भी उचित प्रतिक्रिया नहीं दी गई और प्रशासन ने मामले को अनदेखा किया।

सुप्रबुद्ध सेन का मामला अकेला नहीं है। कलकत्ता हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस शाहिदुल्लाह मुंशी और उनके पूरे परिवार का नाम भी शुरू में मतदाता सूची से हटा दिया गया था। जस्टिस मुंशी ने आरोप लगाया कि नाम हटाने का कोई कारण नहीं बताया गया और दस्तावेज जमा करने पर रसीद तक नहीं दी गई। हालांकि, भारी विरोध और आपत्ति के बाद उनके नाम सूची में वापस जोड़ दिए गए।

इस विवाद ने राज्य की राजनीति में भारी हलचल पैदा कर दी है। विपक्षी दलों ने

निर्वाचन आयोग को घेरा और सवाल उठाया कि क्या सूची तैयार करते समय पक्षपात या लापरवाही हुई। इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। विपक्ष का कहना है कि ऐसे संवेदनशील मामलों में सटीक और पारदर्शी प्रक्रिया का पालन होना चाहिए ताकि किसी भी नागरिक को मतदान के अधिकार से वंचित न किया जा सके।

ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका (PIL) दायर कर इस SIR प्रक्रिया को चुनौती दी थी। याचिका में आरोप लगाया गया कि प्रक्रिया में गंभीर खामियां हैं और बड़ी संख्या में नाम गायब होने या गलत तरीके से हटाए जाने से लोकतांत्रिक अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। आंकड़ों के अनुसार, 900 न्यायिक अधिकारियों ने मात्र 27 कार्य दिवसों में 52 लाख आपत्तियों का निपटारा किया। यानी हर दिन करीब 1.92 लाख मामलों का निपटारा किया गया। इतनी तेज़ गति ने प्रक्रिया की निष्पक्षता और बारीकी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

यह विवाद यह सवाल भी उठाता है कि जब संविधान को सजाने वाले और भारतीय इतिहास के महान कलाकारों के परिवार को मतदाता सूची से हटा दिया जाता है, तो आम नागरिकों के वोट अधिकार की सुरक्षा कितनी सुनिश्चित है। नंदलाल बोस वह व्यक्तित्व थे जिन्हें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान को भारतीय रंग में ढालने की जिम्मेदारी दी थी। उन्होंने रामायण, महाभारत, बुद्ध, महावीर, शिवाजी महाराज और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जैसे महापुरुषों के चित्र बनाकर भारत के गौरवपूर्ण इतिहास को संविधान के पन्नों पर जीवंत किया।

बोस् के परिवार के नाम का गायब होना बंगाल की राजनीति में भावनात्मक मुद्दा बन गया है। इस मुद्दे ने राज्य में सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों के बीच सियासी लड़ाई तेज कर दी है। विपक्ष ने कहा कि यह मामला केवल प्रशासनिक त्रुटि नहीं बल्कि मतदाता सूची में जानबूझकर गड़बड़ी का संकेत है। वहीं, चुनाव आयोग ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है और सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी पात्र मतदाता सूची में शामिल हों।

विशेषज्ञों का मानना है कि मतदाता सूची से नाम हटाना केवल व्यक्तिगत अधिकार का उल्लंघन नहीं है, बल्कि यह लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों पर भी सवाल खड़ा करता है। यदि बड़ी संख्या में नाम गलती या लापरवाही से हटा दिए जाएं, तो यह चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता को प्रभावित कर सकता है।

इस विवाद के बीच चुनाव आयोग ने जोर देकर कहा कि किसी भी मतदाता को मतदान के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा और सभी आपत्तियों का निष्पक्ष और पारदर्शी समाधान किया जाएगा। आयोग ने सुप्रबुद्ध सेन और जस्टिस मुंशी जैसे मामलों की गहन समीक्षा करने के लिए विशेष टीमों का गठन किया है।

राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यह मामला आगामी विधानसभा चुनावों में राज्य की राजनीति में नया मोड़ ला सकता है। मतदाता सूची में गड़बड़ी के आरोपों से जनता के बीच भरोसे का मुद्दा उठ सकता है, और इससे चुनावी रणनीतियों और प्रचार अभियान पर भी असर पड़ सकता है।

अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि किसी भी प्रकार की राजनीतिक या सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने वाली अफवाहों पर ध्यान न दिया जाए और प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से पूरा किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में किसी भी गलती या आपत्ति के लिए कानूनी उपाय उपलब्ध हैं और कोई भी नागरिक अपने मतदाता अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए शिकायत दर्ज कर सकता है।

कुल मिलाकर, नंदलाल बोस के परिवार का नाम मतदाता सूची से गायब होना बंगाल में चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर सवाल खड़ा करता है। यह विवाद राज्य में राजनीतिक और सामाजिक दोनों ही स्तर पर गहरी बहस का विषय बन गया है। चुनाव आयोग और संबंधित प्रशासन अब इस मामले को सुलझाने और सभी पात्र मतदाताओं के अधिकार सुनिश्चित करने के लिए विशेष सतर्कता बरत रहे हैं।

नवसर्जन संस्कृति
हिन्दी

JioTV
CHENNAL NO.
2063

Jio Air Fiber
Jio Tv +
Jio Fiber
Daily Hunt
ebaba Tv
Dish Plus
DTH live OTT
Rock TV
Airtel
Amezone Fire
Rocu Tv-US.UK

देश-दुनिया के नवीनतम समाचार
प्राप्त करने के लिए आज ही
नवसर्जन संस्कृति हिंदी चेनल देखिये

संपादकीय

हरियाणा-हिमाचल के फार्मा उद्योग पर मार

खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका, इस्राइल और ईरान के बीच बढ़ता संघर्ष अब केवल एक क्षेत्रीय या सामरिक टकराव नहीं रह गया है, बल्कि इसका प्रभाव वैश्विक अर्थव्यवस्था के अनेक महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है। भारत भी इससे अछूता नहीं है, विशेष रूप से दवा उद्योग, जो देश की अर्थव्यवस्था और वैश्विक स्वास्थ्य व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में स्थापित है। हिमाचल प्रदेश और हरियाणा जैसे राज्य, जहां दवा निर्माण की सैकड़ों लघु एवं मध्यम इकाइयाँ कार्यरत हैं, इस संकट के प्रत्यक्ष प्रभाव को झेल रहे हैं। दरअसल, दवा उद्योग का आधार कच्चे माल की निरंतर और सस्ती उपलब्धता पर टिका होता है। फार्मास्यूटिकल उत्पादों के निर्माण में उपयोग होने वाले एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रीडिएंट्स (API), विभिन्न प्रकार के सॉल्वैंट्स और पेट्रोकेमिकल आधारित डेरिवेटिव्स का एक बड़ा हिस्सा या तो सीधे पश्चिम एशिया से आता है या उन्हीं समुद्री मार्गों से होकर भारत पहुँचता है। वर्तमान संघर्ष के कारण इन समुद्री मार्गों पर असुरक्षा, देरी और परिवहन लागत में अत्यधिक वृद्धि देखने को मिल रही है। जहाजों के बीमा प्रीमियम में वृद्धि, मार्ग परिवर्तन और ईंधन लागत में उतार-चढ़ाव ने पूरी आपूर्ति श्रृंखला को अस्थिर कर दिया है।

इसका सीधा असर कच्चे माल की कीमतों पर पड़ा है, जो कई मामलों में 20 से 30 प्रतिशत तक बढ़ चुकी हैं। विशेष रूप से पेट्रोलियम आधारित पैकेजिंग सामग्री जैसे प्लास्टिक कंटेनर, ब्लिस्टर पैक और अन्य पैकिंग उत्पादों की कीमतों में तेज उछाल आया है। इससे उत्पादन लागत में भारी वृद्धि हुई है। पहले से ही कम मार्जिन पर काम कर रही लघु एवं मध्यम दवा इकाइयाँ अब आर्थिक दबाव के गंभीर दौर से गुजर रही हैं। कई इकाइयों के सामने उत्पादन घटाने या अस्थायी रूप से बंद करने जैसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो रही हैं। हालांकि, यह संकट केवल आर्थिक या औद्योगिक नहीं है, बल्कि इसका सामाजिक पहलू भी उतना ही गंभीर है। इन दवा उद्योगों की रीढ़ प्रवासी श्रमिक हैं, जो विभिन्न राज्यों से आकर इन इकाइयों में कार्य करते हैं। वर्तमान अस्थिरता के माहौल में ये श्रमिक खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ईंधन संकट और घरेलू उपयोग के लिए एलपीजी की आपूर्ति में बाधा ने उनके दैनिक जीवन को प्रभावित किया है। बढ़ती महंगाई और अनिश्चित रोजगार की स्थिति ने उनके मनोबल को कमजोर किया है, जिसका सीधा असर उनकी उत्पादकता पर पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश के बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ (BBN) क्षेत्र और हरियाणा के प्रमुख फार्मा क्लस्टर्स इस दोहरे संकट का सामना कर रहे हैं। एक ओर उत्पादन लागत में वृद्धि है, तो दूसरी ओर श्रमिकों की अस्थिरता के कारण उत्पादन में निरंतरता बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो गया है। छोटे निर्माताओं के लिए यह स्थिति और भी कठिन है, क्योंकि उनके पास न तो बड़े भंडारण की सुविधा होती है और न ही वे लंबे समय तक घाटा सहने की क्षमता रखते हैं। इसके अतिरिक्त, बढ़ती लागत और वैश्विक परिवहन खर्चों के कारण भारतीय दवा उद्योग की निर्यात प्रतिस्पर्धा भी प्रभावित हो रही है। भारत, जो "फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड" के रूप में जाना जाता है, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाओं के निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन जब उत्पादन लागत बढ़ती है, तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा बनाए रखना कठिन हो जाता है। इससे न केवल निर्यात में गिरावट आ सकती है, बल्कि भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा पर भी असर पड़ सकता है। यह संकट भारत की आयात पर अत्यधिक निर्भरता की कमजोरी को भी उजागर करता है। विशेष रूप से API के मामले में भारत लंबे समय से चीन और अन्य बाहरी स्रोतों पर निर्भर रहा है। हालांकि, सरकार ने आत्मनिर्भरता की दिशा में कई पहलें शुरू की हैं, जैसे कि API पार्कों की स्थापना और उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाएँ (PLI), लेकिन इनका प्रभाव अभी व्यापक स्तर पर दिखना बाकी है। वर्तमान परिस्थिति यह संकेत देती है कि भारत को अपनी औद्योगिक नीति में दीर्घकालिक और रणनीतिक बदलाव करने की आवश्यकता है। कच्चे माल के वैकल्पिक स्रोतों की खोज, घरेलू उत्पादन क्षमता में वृद्धि और आपूर्ति श्रृंखला का विविधीकरण अत्यंत आवश्यक है। इसके साथ ही, प्रवासी श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा, स्थिर रोजगार और जीवन-यापन की सुविधाओं को सुनिश्चित करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अंततः, खाड़ी क्षेत्र में चल रहा यह संघर्ष भारत के लिए एक चेतावनी के रूप में देखा जाना चाहिए। यह केवल एक दूरस्थ युद्ध नहीं है, बल्कि इसके प्रभाव भारत की अर्थव्यवस्था, उद्योग और समाज के विभिन्न स्तरों तक पहुँच रहे हैं। दवा उद्योग, जो मानव जीवन से सीधे जुड़ा है, इस चुनौती के केंद्र में खड़ा है। ऐसे में आवश्यक है कि सरकार, उद्योग और समाज मिलकर इस संकट का समाधान खोजें, ताकि भविष्य में इस प्रकार की वैश्विक अस्थिरताओं का प्रभाव न्यूनतम किया जा सके और देश की आर्थिक एवं औद्योगिक स्थिरता बनी रहे।

भीतरी अदालत का न्याय संवारेगा जीवन

> "सही मायनों में मन की अदालत में हमारा पाक-साफ होना, हमारी आत्मा के परिष्कार का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। वास्तव में बाहरी सफलता हमारी उपलब्धि नहीं होती। उपलब्धि यह है कि हमारी कारगुजारियों से हमें खुद शर्मिंदा न होना पड़े।

आए दिन समाज में ऐसी खबरें आती हैं कि धनाढ्य और जीवन में सफल लोगों का व्यक्तिगत जीवन भी अशांत है। वे न केवल शारीरिक रूप से ही अस्वस्थ थे बल्कि मानसिक रूप से भी उतने ही अशांत होते हैं। जीवन में तमाम कामयाबियों व धन-दौलत जुटाने के बाद भी ऐसे लोगों को नींद नहीं आती। हमारी नींद का सीधा रिश्ता हमारे कार्यों की गुणवत्ता और जीवन की सहजता से होता है। मानवीय श्रम भी उसका एक बड़ा कारक है। धारणा बनने लगी है कि आज के गलाकाट स्पर्धा दौर में तुरंत सफलता व संपदा खालिस मेहनत-ईमानदारी से हासिल नहीं होती। एक व्यापारी को अपने मुनाफे के लिए दिन में सौ बार झूठ बोलना पड़ता है। रात को जब वह बिस्तर में सोने जाता है तो दिनभर के खटकर्म उसे सोने नहीं देते। उसके अंतर्मन की अदालत उसके कृत्यों का हिसाब-किताब मांगती है। व्यक्ति चाहकर भी अपनी दौलत, शोहरत और सुख-सुविधाओं का सुख नहीं भोग पाता है। वास्तव में जिसे हम सफलता मानते हैं वह बाहरी दुनिया का बहलावा मात्र है। जरूरी नहीं कि वह हमें सुख और मानसिक शांति भी दे।

व्यक्ति जब भी कोई अन्याय या शोषण करता है तो उसका अंतर्मन उसे सचेत करता है। उसे अहसास कराता है कि क्या सही है और क्या गलत है। मनुष्य की भीतरी चेतना उसे गलत के प्रति सचेत करती है। अच्छा इंसान व संत तो इसे सुनकर अपनी नीति व कार्यशैली का निर्धारण करता है, लेकिन संवेदना खो चुका व्यक्ति इसे नजरअंदाज कर देता है। सही मायनों में हर व्यक्ति के भीतर यह न्याय व्यवस्था निरंतर चलती रहती है। वैसे तो दुनियावी अदालतें भी न्याय देने का काम करती हैं। न्याय करने वाले गवाहों व सबूतों के साथ तर्क-वितर्कों का सहारा लेकर किसी नतीजे पर पहुंचते हैं। अक्सर वहां साक्ष्यों को अपनी सुविधा के अनुसार ढाला जाता है। हलफनामे भी संदिग्ध हो सकते हैं और दलीलें भी झूठी हो सकती हैं। इस प्रपंच में कई बार न्याय मृगमारीचिका बनकर रह जाता है।

मगर हमारे भीतर चलने वाली मौन अदालत की प्रकृति इस बाहरी व्यवस्था से एकदम भिन्न होती है। हमारे कर्मों का लेखाजोखा हमारे चित्त के पटल पर अंकित हो जाता है। बिना किसी हेरफेर के हमारे कर्मों की चार्जशीट तैयार हो जाती है। मन की अदालत के कटघरे में अभियुक्त भी हम ही होते हैं। हमारे अंतर्मन का विवेक एक चश्मदीद गवाह की तरह मन की अदालत में हमारे कृत्यों की गवाही देता है। न्याय करने के लिए हमारी चेतना न्यायमूर्ति के रूप में न्याय की कुर्सी पर विराजमान होती है। ऐसे में व्यक्ति की बहानेबाजी व चतुर चालाकियां धरी की धरी रह जाती हैं। कभी न कभी व्यक्ति को अपवित्र कृत्यों को लेकर अपराधबोध होता ही है।

भले ही मन की अदालत लौकिक दंड जैसी सजा न सुनाए मगर इसके अपराधबोध से व्यक्ति जीवनपर्यंत उबर नहीं पाता। उसे आत्मग्लनि का त्रास झेलना ही पड़ता है। यही कसक उसे रातभर चैन से नहीं सोने देती।

हम अंतर्मन की अदालत में पाक साफ निकलें इसके लिये जरूरी है कि हमारा मन निर्मल हो। जैसे कि सही मायने में एक बच्चे और संत का निष्कपट व निर्मल मन होता है। जो ईर्ष्या, द्वेष, कटुता और चतुराई से मुक्त होता है। एक सच्चा साधक भी निर्मल मन से ईश्वर की साधना कर पाता है, जिसके लिए सदियों से साधु-संत पूजा-पाठ, सत्संग, स्वाध्याय, ध्यान व साधना आदि का सहारा लेते हैं। ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग निर्मल मन से होकर जाता है। इस निर्मलता का अहसास हमें हमारे तीर्थों व शक्तिपीठों में गहरे तक होता है।

निर्मल मन का व्यक्ति वह होता है जो दुनियावी मोह-माया व चतुर-चालाकियों के प्रति निरपेक्ष रहकर दुनिया को साक्षी भाव से देखता है। यही निर्लिप्तता उसके अंतर्मन को निर्मल रखती है। योगशास्त्र में वर्णित यम-नियम का उपयोग इसी राह में आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करता है। अष्टांग योग में वर्णित पांच यम—सत्य, अहिंसा अस्तेय, ब्रह्मचर्य व अपरिग्रह तथा पांच नियम—शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय व ईश्वर प्राणिधान जीवन की निर्मलता का मार्ग प्रशस्त करते हैं। व्यक्ति के अंतःकरण की शुद्धि का कार्य करते हैं।

सवाल उठता है कि दुनियावी दौड़भाग में लगे एक सामान्य आदमी के लिए अपने मन को बेदाग रखने का सरल मार्ग क्या हो सकता है? सही मायनों में सहजता और निश्छलता से जीना ही वह मार्ग है, जो हमें मन की अदालत में निर्दोष साबित कर सकता है। हम देश-काल परिस्थितियों में व मानवीय दुर्बलताओं के चलते पथ से भटक सकते हैं। लेकिन हम में अपराधों को स्वीकार करने का माद्दा होना चाहिए। इससे बचने की दलीलें हमारे मन को कलुषित कर सकती हैं। जिसके लिए हमें अपने दिन-भर के कृत्यों को लेकर आत्ममंथन करना भी जरूरी है।

सही मायनों में मन की अदालत में हमारा पाक-साफ होना, हमारी आत्मा के परिष्कार का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। वास्तव में बाहरी सफलता हमारी उपलब्धि नहीं होती। उपलब्धि यह है कि हमारी कारगुजारियों से हमें खुद शर्मिंदा न होना पड़े।

प्रेरणा

धर्म की रक्षा में अमर बलिदानः गुरु तेग बहादुर का अद्वितीय साहस और सनातन चेतना

सन 1675 का भारत इतिहास के उन कठिनतम दौरों में से एक था, जब औरंगजेब के शासन में धार्मिक असहिष्णुता अपने चरम पर थी। पूरे देश में विशेष रूप से हिन्दुओं पर धर्म परिवर्तन का दबाव बढ़ता जा रहा था। जजिया कर जैसे आर्थिक बोझ और तरह-तरह के दमनकारी आदेशों के माध्यम से समाज को तोड़ने और झुकाने का प्रयास किया जा रहा था। मंदिरों को ध्वस्त करने के आदेश, सार्वजनिक रूप से पर्व-त्योहारों पर रोक और आस्था के प्रतीकों का अपमान—ये सब उस समय की भयावह वास्तविकताएं थीं। काशी के भगवान विश्वनाथ, गुजरात के सोमनाथ और मथुरा के श्रीकेशव राय मंदिरों को तोड़े जाने के आदेश ने पूरे भारतवर्ष में भय और आक्रोश का वातावरण उत्पन्न कर दिया था। ऐसा प्रतीत होने लगा था मानो सनातन धर्म स्वयं अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा हो।

इसी विकट परिस्थिति में एक महान विभूति का उदय हुआ, जिनका जीवन केवल एक व्यक्ति का जीवन नहीं, बल्कि एक युग की चेतना बन गया। गुरु तेग बहादुर का जन्म वैशाख कृष्ण पक्ष पंचमी, विक्रमी संवत 1678 को अमृतसर में हुआ था। वे गुरु हरगोबिंद साहिब और माता नानकी जी के सबसे छोटे पुत्र थे। बचपन से ही वे अत्यंत शांत, गंभीर और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे। जहां अन्य बच्चे खेल-कूद में लगे रहते थे, वहीं तेग बहादुर एकांत में बैठकर ध्यान, चिंतन और आत्ममंथन में लीन रहते थे। उनकी यह प्रवृत्ति साधारण नहीं थी, बल्कि भविष्य के एक महान तपस्वी और धर्मरक्षक की झलक थी।

गुरु तेग बहादुर केवल एक संत ही नहीं, बल्कि एक महान योद्धा भी थे। उन्होंने कम आयु में ही युद्धकला, घुड़सवारी, तलवारबाजी और निशानेबाजी में दक्षता प्राप्त कर ली थी। करतारपुर की लड़ाई में उनके अद्भुत पराक्रम को देखकर ही उन्हें 'तेग बहादुर' की उपाधि दी गई। लेकिन उनका जीवन केवल युद्ध तक सीमित नहीं था, बल्कि उसमें सेवा, त्याग और आध्यात्मिकता का अद्भुत संगम था। उन्होंने शास्त्रीय संगीत, गुरबानी और भारतीय पौराणिक ज्ञान का भी गहन अध्ययन किया, जिससे उनका व्यक्तित्व और भी व्यापक और प्रभावशाली बन गया।

उस समय कश्मीर के हिन्दुओं की स्थिति अत्यंत दयनीय हो चुकी थी। उन्हें जबरन इस्लाम स्वीकार करने के लिए मजबूर किया जा रहा था। जो लोग इसका विरोध करते, उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता या उनकी संपत्ति लूट ली जाती। इस अमानवीय अत्याचार से त्रस्त होकर कश्मीरी पंडितों का एक समूह गुरु तेग बहादुर की शरण में पहुंचा। उन्होंने अपनी पीड़ा सुनाई और धर्म की रक्षा के लिए सहायता मांगी। यह केवल एक समुदाय की पुकार नहीं थी, बल्कि पूरी मानवता की आवाज थी।

गुरु तेग बहादुर ने इस पुकार को केवल एक याचना नहीं, बल्कि अपना कर्तव्य समझा। उन्होंने यह निश्चय किया कि वे अन्याय के सामने झुकेंगे नहीं, बल्कि उसका डटकर सामना करेंगे। वे मुगलों के दरबार में पहुंचे और औरंगजेब को समझाने का प्रयास किया कि धर्म किसी पर थोपने की वस्तु नहीं है। लेकिन सत्ता के अहंकार में डूबे औरंगजेब ने उनकी बातों को नकार दिया और उनके सामने तीन विकल्प रखे—इस्लाम स्वीकार करना, कोई चमत्कार दिखाना या फिर मृत्यु को स्वीकार करना।

यह वह क्षण था जब इतिहास ने एक महान निर्णय का साक्षी बनने का अवसर पाया। गुरु तेग बहादुर ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि धर्म केवल पूजा-पद्धति नहीं, बल्कि जीवन का सत्य और आत्मा की स्वतंत्रता है। उन्होंने कहा कि किसी भी धर्म को बलपूर्वक थोपना अधर्म है और इसे स्वीकार करना आत्मा के साथ विश्वासघात होगा। उन्होंने चमत्कार दिखाने से भी इनकार किया, क्योंकि वह ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध होता। अंततः उन्होंने शहादत को चुना—एक ऐसा निर्णय जो न केवल उनके जीवन का, बल्कि पूरे भारतीय इतिहास का सबसे गौरवपूर्ण क्षण बन गया।

दिल्ली के चांदनी चौक में, जहां आज गुरुद्वारा शीशगंज साहिब स्थित है, वहीं पर गुरु तेग बहादुर का बलिदान हुआ। उनके शीश को उनके शरीर से अलग कर दिया गया, लेकिन उनकी आस्था, उनका साहस और उनका संदेश आज भी अमर है। उनका यह बलिदान केवल सिख धर्म के लिए नहीं था, बल्कि संपूर्ण सनातन संस्कृति और धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए था।

गुरु तेग बहादुर का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्चा धर्म वही है, जो सत्य, न्याय और मानवता की रक्षा करता है। उन्होंने यह सिद्ध किया कि धर्म किसी एक समुदाय की संपत्ति नहीं, बल्कि पूरी मानवता का अधिकार है। उनका बलिदान हमें यह प्रेरणा देता है कि अन्याय के सामने कभी झुकना नहीं चाहिए, चाहे उसके लिए कितनी भी बड़ी कीमत क्यों न चुकानी पड़े।

आज जब हम आधुनिक भारत में स्वतंत्रता और अधिकारों की बात करते हैं, तब हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह स्वतंत्रता हमें ऐसे ही महान बलिदानों के कारण मिली है। गुरु तेग बहादुर का जीवन केवल इतिहास का एक अध्याय नहीं, बल्कि एक प्रेरणा है—एक ऐसी प्रेरणा जो हमें अपने कर्तव्यों, अपने धर्म और अपने मूल्यों के प्रति सजग रहने की सीख देती है।

हमारी मातृभूमि सदैव ऐसे ही वीरों के त्याग और बलिदान से गौरवान्वित रही है। गुरु तेग बहादुर का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय था। उन्होंने हमें सिखाया कि धर्म का अर्थ केवल पूजा नहीं, बल्कि सत्य और न्याय के लिए खड़ा होना है। उनका जीवन और उनका बलिदान हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, जिसे हमें न केवल याद रखना चाहिए, बल्कि अपने जीवन में उतारना भी चाहिए।

प्रधानमंत्री 'नरेन्द्र मोदी' के नेतृत्व में सफलता के नित-नए आयाम स्थापित करती 'भाजपा'

भारत को एक समर्थ शक्तिशाली राष्ट्र बनाने के लक्ष्य के साथ राष्ट्र को प्रथम मानने का दावा करने वाले राजनेताओं के एक समूह ने वर्ष 1980 में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का गठन किया था। भाजपा का गठन नई दिल्ली के कोटला मैदान में 6 अप्रैल 1980 को आयोजित एक कार्यकर्ता अधिवेशन में तत्कालीन दिग्गज नेताओं की उपस्थिति किया गया था। उस वक्त भाजपा के प्रथम अध्यक्ष के रूप में लोकप्रिय नेता अटल बिहारी वाजपेयी निर्वाचित हुए थे, जो बाद में देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे थे। भाजपा नेतृत्व व कार्यकर्ताओं ने सनातन धर्म संस्कृति परंपराओं को अपनाते हुए, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद एवं लोकहित के विषयों पर कांग्रेस के प्रति मुखर रहते हुए उसको जनता की अदालत में घेरकर के भारतीय लोकतंत्र में अपनी एक अलग ही विशिष्ट पहचान बनाते हुए सशक्त भागीदारी दर्ज करते हुए देश की राजनीति को नए आयाम देने का कार्य किया है। जनता पार्टी की गठबंधन वाली सरकार के दौर के बाद से ही भाजपा नेता अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी आदि ने दिन-रात मेहनत करके भाजपा को अपने पैरों पर खड़ा होने लायक़ बनाया और भाजपा ने अपना पहला लोकसभा चुनाव वर्ष 1984 में लड़ा था, जिसमें उसने 2 सीटों पर जीती हासिल करके भाजपा ने खाता खोला था। उसके बाद भाजपा के नेता लालकृष्ण आडवाणी अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के मुद्दे को जोर-शोर से उठाया, जिसके चलते उस वक्त भाजपा की देश के कई राज्यों में सरकार बनी और भाजपा को कल्याण सिंह जैसा फॉयर ब्रांड राजनेता मिला था। शीर्ष नेतृत्व व कार्यकर्ताओं की वर्षों की मेहनत के दम पर ही वर्ष 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी को गठबंधन सरकार का नेतृत्व करने का अवसर मिला था। जिसके बाद भाजपा ने अपनी जड़ें देश के अधिकांश हिस्सों में जमाने के लिए कार्य तेज़ी से करना शुरू किया था।

अटल युग के बाद 10 वर्ष तक केन्द्र में विपक्ष में बैठने के लंबे वनवास के बाद वर्ष 2014 में प्रचंड बहुमत के साथ नरेन्द्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। भाजपा में यह नरेन्द्र मोदी व अमित शाह के युग जबरदस्त ढंग से प्रारंभ था। मोदी-शाह के इस दौर में भाजपा ने राजनीति के नित-नए कीर्तिमान स्थापित किए, अपने लोकप्रिय राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के नेतृत्व में लगभग 11 करोड़ सदस्य बनाकर के विश्व की सबसे बड़ी राजनैतिक पार्टी बनने का खिताब हासिल किया। वहीं मोदी-शाह की इस जोड़ी ने आज भी अपनी चाणक्य नीति व देश में विकास पर आधारित राजनीति की मजबूत नींव रखकर विपक्षी दलों की नींद उड़ाने का काम कर रखा है। आज देश में देश में दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, नगालैंड, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, बिहार और आंध्र प्रदेश में भाजपा या एनडीए सरकार हैं। देशभर में भारतीय जनता पार्टी के पास लगभग सर्वाधिक 1654 विधायक हो गए हैं। भाजपा के पास लगभग 240 लोकसभा सांसद हैं, वहीं लगभग 106 राज्यसभा सांसद हैं। देश की राजनीति में मोदी-शाह की जोड़ी का जलवा कायम है, विपक्षी दल उनकी राजनीति की काट नहीं ढूंढ पा रहे हैं। जिसके चलते देश के हृदय गुजरात, हरियाणा, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, दिल्ली, राजस्थान आदि राज्यों में भाजपा काबिज है, केन्द्र के साथ कई राज्यों में भाजपा लगातार सरकार बनाने में सफल हो रही है।

बहुत सारे लोगों का मानना है कि देश में आम लोगों को मोदी राज में विकास कार्यों का बड़ा सकारात्मक परिवर्तन धरातल पर नज़र आने लगा है। देश के विश्वस्तरीय नव निर्माण के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत तेज़ी से कार्य चल रहे हैं। मोदी सरकार एक सुदृढ़, सशक्त, समृद्ध, समर्थ एवं स्वावलम्बी भारत के निर्माण हेतु निरंतर सक्रिय है। वह भारत को 'विश्व गुरू' के रूप में विश्व पटल पर स्थापित करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। मोदी भारत को विश्व के विभिन्न राष्ट्रों को प्रभावित करने की क्षमता विकसित करने के लिए निरंतर कार्य कर रहे है। देश में आज भाजपा एक ऐसे प्रमुख राष्ट्रवादी दल के रूप में उभर कर सामने आ रही है जिस दल का लक्ष्य देश में सुशासन, विकास, एकता एवं अखंडता के लिए कार्य करना है। 26 मई, 2014 को नरेन्द्र मोदी ने जब से भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण की है तब से ही मोदी सरकार ने अपनी अनेक योजनाओं के माध्यम से देश में नव निर्माण के एक नए युग की शुरुआत की है। आज मोदी सरकार की नीतियां आम जनमानस के बीच लोकप्रिय हैं, मोदी सरकार की योजनाएं अन्त्योदय, सुशासन, विकास एवं समृद्धि के रास्ते पर देश को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही हैं। आम लोगों को आर्थिक और सामाजिक सुधार से परिपूर्ण सुरक्षित जीवन जीने का मार्ग उपलब्ध करा रही हैं। किसानों के लिये ऋण से लेकर खाद तक की नयी नीतियां जैसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, सॉयल हेल्थ कार्ड, आदि ने कृषि के तीव्र विकास की देशभर में एक नयी अलख जगायी है। आम जनमानस के बीच मोदी सरकार के दौर को एक नये युग के रूप में देखा जा रहा है। भाजपा की मोदी सरकार सुशासन, आदर्श ग्राम योजना, स्वच्छता अभियान, योग के सहारे भारत को स्वस्थ्य बनाने का अभियान आदि से देश को एक नयी ऊर्जा देने का कार्य कर रही है। भाजपा की मोदी सरकार ने मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, अमृत मिशन, दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना, डिजिटल इंडिया आदि जैसी योजनाओं से भारत को आधुनिक और सशक्त बनाने की दिशा में मजबूत कदम उठाया है। जनधन योजना, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना जैसी अनेक योजनाएं देश में एक नयी क्रांति का सूत्रपात कर रही हैं। वहीं राम मंदिर निर्माण, धारा 370 की समाप्ति व पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देकर भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने अपनी पैठ आम जनमानस के बीच और मजबूत करने का काम किया है। भाजपा के तेजतर्रार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर न्याय और हेमंत बिस्वा शर्मा की कार्यशैली की पूरे देश में चर्चा है।

अभियान

गंगाः जीवन, आस्था और सभ्यता की अनंत बहती धारा का अमर सत्य

भारत की पहचान केवल उसके भूगोल, इतिहास या विविधताओं से नहीं होती, बल्कि उसकी आत्मा उन प्रतीकों में बसती है जो सदियों से जीवन को दिशा देते आए हैं। गंगा ऐसी ही एक अनंत, अविरल और पवित्र धारा है, जो केवल एक नदी नहीं, बल्कि भारतीय सभ्यता, संस्कृति और आध्यात्मिक चेतना का मूल स्रोत है। गंगा को 'मां' कहकर पुकारना केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि उस गहरे भाव का प्रतीक है जिसमें प्रकृति को जीवनदायिनी और पोषक के रूप में देखा जाता है। यह वही धारा है जिसने अनादि काल से धरती को पल्लवित और पुष्पित किया, मानव जीवन को ऊर्जा दी और आत्मा को शुद्ध करने का मार्ग प्रदान किया।

गंगा के बिना भारत की कल्पना करना लगभग असंभव है। यह नदी केवल जल का स्रोत नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था, विश्वास और जीवनयापन का आधार है। इसके किनारे ही वैदिक सभ्यता का विकास हुआ, जहां ऋषि-मुनियों ने वेदों का उच्चारण किया, उपनिषदों की रचना की और जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझने का प्रयास किया। गंगा के तटों पर ही धर्म, दर्शन और संस्कृति की वह नींव रखी गई, जिसने भारत को विश्व में एक विशिष्ट पहचान दिलाई। इसीलिए गंगा को केवल एक भौगोलिक धारा नहीं, बल्कि ज्ञान, परंपरा और आध्यात्मिकता की जीवंत धारा कहा जाता है।

प्राचीन ग्रंथों में गंगा की महिमा का विस्तृत वर्णन मिलता है। ऋग्वेद से लेकर रामायण, महाभारत और पुराणों तक, हर जगह गंगा को पवित्रता और मोक्ष की प्रतीक माना गया है। गंगा लहरी जैसे ग्रंथों में इसकी स्तुति करते हुए इसे दिव्य और अलौकिक शक्ति का रूप बताया गया है। भगवान श्रीकृष्ण ने गीता में स्वयं को जल स्रोतों में 'जाह्नवी गंगा' कहा है, जो इस नदी की महत्ता को और भी अधिक प्रतिष्ठित करता है। गंगा का जल केवल शरीर को शुद्ध नहीं करता, बल्कि मन और आत्मा को भी पवित्र करने की शक्ति रखता है—यह विश्वास भारतीय जनमानस में गहराई से समाया हुआ है।

गंगा का पृथ्वी पर अवतरण भी एक अत्यंत प्रेरणादायक कथा से जुड़ा हुआ है। राजा सगर के साठ हजार पुत्रों के उद्धार के लिए उनके वंशज राजा भगीरथ ने कठोर तपस्या की। उनकी अटूट साधना से प्रसन्न होकर गंगा ने पृथ्वी पर आने का निर्णय लिया, लेकिन उनकी प्रचंड धारा को धारण करना किसी के लिए संभव नहीं था। तब भगवान शिव ने अपनी जटाओं में गंगा को समाहित कर उसके वेग को नियंत्रित किया और धीरे-धीरे पृथ्वी पर प्रवाहित किया। यह कथा केवल एक धार्मिक आख्यान नहीं, बल्कि यह दर्शाती है कि महान उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए धैर्य, तप और समर्पण कितना आवश्यक है।

गंगोत्री वह पवित्र स्थल है, जहां गंगा ने पहली बार पृथ्वी को स्पर्श किया। हिमालय की गोद में स्थित यह स्थान न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि प्राकृतिक सौंदर्य का भी अनुपम उदाहरण है। गोमुख से निकलकर गंगा की धारा आगे बढ़ती है और अपने मार्ग में अनेक सहायक नदियों को अपने में समाहित करती हुई विशाल रूप धारण कर लेती है। यह यात्रा केवल जल की नहीं, बल्कि जीवन और संस्कृति के विस्तार की यात्रा है।

गंगा के मार्ग में आने वाले विभिन्न संगम स्थल भारतीय संस्कृति में विशेष महत्व रखते हैं। जहां-जहां नदियों का मिलन होता है, वहां आस्था का एक नया आयाम जुड़ जाता है। त्रिवेणी संगम, जहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का मिलन होता है, वह स्थान करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए मोक्ष का द्वार माना जाता है। कुंभ और अर्धकुंभ जैसे महापर्वों में यहां लाखों लोग स्नान कर अपने जीवन को धन्य मानते हैं। यह दृश्य केवल धार्मिक आस्था का नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक एकता का भी प्रतीक है।

गंगा का महत्व केवल आध्यात्मिक या धार्मिक नहीं है, बल्कि यह भारत की आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था की भी रीढ़ है। इसके जल से विशाल कृषि क्षेत्र सिंचित होते हैं, जिससे करोड़ों लोगों की आजीविका चलती है। गंगा के किनारे बसे शहर और गांव न केवल व्यापार और रोजगार के केंद्र हैं, बल्कि सांस्कृतिक गतिविधियों के भी प्रमुख स्थल हैं। वाराणसी, हरिद्वार, प्रयागराज और कोलकाता जैसे शहर गंगा के कारण ही विश्वभर में अपनी पहचान बनाए हुए हैं।

गंगा के किनारे जीवन की एक अलग ही लय देखने को मिलती है। सुबह की आरती, शाम की गंगा आरती, तटों पर होने वाले धार्मिक अनुष्ठान और साधु-संतों की तपस्या—ये सभी दृश्य इस नदी को केवल एक भौतिक अस्तित्व से कहीं अधिक बना देते हैं। यहां आकर व्यक्ति केवल जल में स्नान नहीं करता, बल्कि अपने भीतर की अशुद्धियों को भी धोने का प्रयास करता है। यही कारण है कि गंगा को मोक्षदायिनी कहा जाता है।

लेकिन आधुनिक समय में गंगा के सामने कई गंभीर चुनौतियां भी खड़ी हो गई हैं। औद्योगीकरण, शहरीकरण और बढ़ते प्रदूषण ने इसकी निर्मलता को प्रभावित किया है। नदियों में गिरने वाले अपशिष्ट, प्लास्टिक और रासायनिक तत्वों ने इसके जल को दूषित कर दिया है। यह स्थिति केवल पर्यावरण के लिए ही नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत के लिए भी खतरा है। यदि गंगा की शुद्धता नष्ट होती है, तो यह केवल एक नदी का नहीं, बल्कि हमारी पहचान का भी नुकसान होगा।

इस चुनौती से निपटने के लिए सरकार और समाज दोनों स्तरों पर प्रयास किए जा रहे हैं। गंगा को स्वच्छ और अविरल बनाए रखने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन इन प्रयासों की सफलता तभी संभव है जब हर नागरिक अपनी जिम्मेदारी को समझे। गंगा की रक्षा केवल सरकार का कार्य नहीं, बल्कि हम सभी का कर्तव्य है।

गंगा हमें केवल जीवन नहीं देती, बल्कि जीवन जीने की कला भी सिखाती है। इसकी अविरल धारा हमें निरंतर आगे बढ़ने का संदेश देती है, इसकी पवित्रता हमें अपने विचारों को शुद्ध रखने की प्रेरणा देती है और इसका समर्पण हमें निस्वार्थ सेवा का मार्ग दिखाता है। यही कारण है कि गंगा केवल एक नदी नहीं, बल्कि एक जीवंत दर्शन है, जो हर युग में मानवता को दिशा देता आया है।

अंततः, गंगा भारत की आत्मा है, उसकी पहचान है और उसकी सांस्कृतिक धरोहर है। यह वह धारा है जो अतीत, वर्तमान और भविष्य को जोड़ती है। इसके जल में केवल जीवन नहीं, बल्कि इतिहास, परंपरा और आस्था का अमूल्य संगम है। मां गंगा का सम्मान करना, उनकी रक्षा करना और उनकी पवित्रता को बनाए रखना हम सभी का कर्तव्य है, क्योंकि यही वह धारा है जो हमें हमारे अस्तित्व से जोड़ती है और हमें जीवन का वास्तविक अर्थ समझाती है।

RNI No. GJHIN/25/A2786 Printed, Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424. Editor : JIGNESHKUMAR PATHABHAI VAGHELA
Regd.Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424 Gujarat,India. Phone : (o) 7698333307 (M) 8485951747,7096333307
Email:navsarjansanskruti2016@gmail.com*navsarjansanskruti2016@yahoo.com*Website : www.navsarjansanskruti.com

राजकोट में चुनाव सुरक्षा के मद्देनज़र हथियार जमा करने के आदेश

राजकोट। आगामी स्थानीय स्वशासन चुनाव 2026 को देखते हुए राजकोट सिटी पुलिस कमिश्नरेट ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने और चुनावी प्रक्रिया को सुरक्षित बनाने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। पुलिस कमिश्नर ब्रजेश कुमार झा ने आदेश दिया है कि आदर्श आचार संहिता लागू क्षेत्रों में सभी लाइसेंसधारी हथियारों को अनिवार्य रूप से संबंधित पुलिस थानों में जमा कराना होगा। यह कदम इस बात को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है कि चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार की हिंसा या अवैध गतिविधियों की संभावना न्यूनतम हो।

यह आदेश राज्य में हो रहे चुनावों के संदर्भ में जारी किया गया है। इसमें 15 नगर निगम, 84 नगरपालिका, 34 जिला पंचायत और 260 तालुका पंचायत के आम चुनाव शामिल हैं। इसके अलावा, 11 नगर निगमों की 13 रिक्त सीटों पर होने वाले उपचुनाव भी इस आदेश के दायरे में आते हैं। पुलिस कमिश्नरेट ने सभी संबंधित थानों को निर्देश दिया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में लाइसेंसधारकों से हथियार जमा कराने की कार्रवाई सुनिश्चित करें और पूरी जानकारी कमिश्नरेट को उपलब्ध कराएं।

पुलिस कमिश्नरेट ने आदेश में स्पष्ट किया है कि चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक लाइसेंस प्राप्त हथियारों के सार्वजनिक प्रदर्शन और किसी भी प्रकार के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश उन सभी लाइसेंसधारकों पर लागू होगा, चाहे उनका लाइसेंस राजकोट से जारी हुआ हो या किसी अन्य प्राधिकरण से। इसके अलावा, चुनाव प्रक्रिया के दौरान हथियारों की खरीद-फरोख्त पर भी अस्थायी रोक लगा दी गई है। हालांकि, चुनाव समाप्त होने के बाद 30 अप्रैल 2026 के पश्चात जमा किए गए हथियार संबंधित पुलिस थानों द्वारा बिना किसी अतिरिक्त आदेश के वापस कर दिए जाएंगे।

कुछ विशेष श्रेणियों को इस आदेश से छूट दी गई है। इनमें सरकारी और अर्ध-सरकारी संस्थान, बैंक, निगम, मान्यता प्राप्त सुरक्षा एजेंसियों के गनमैन, एटीएम और करेंसी चेस्ट की सुरक्षा में लगे कर्मी, तथा राज्य, राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्तर के निशानेबाज शामिल हैं। हालांकि, व्यक्तिगत नाम से जारी लाइसेंसधारकों को इस छूट का लाभ नहीं मिलेगा। सुरक्षा गार्डों को अपने साथ बैंक प्रबंधक द्वारा जारी प्रमाण पत्र रखना अनिवार्य होगा, जिसमें उनकी पहचान और नियुक्ति का विवरण शामिल होगा। संबंधित बैंक प्रबंधन को ऐसे कर्मचारियों की जानकारी पुलिस स्टेशन को देनी होगी, जिसकी पुलिस द्वारा सत्यापन किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारी तथा कर्मचारी, जिन्हें कानून के तहत हथियार रखने की अनुमति है और जो चुनाव ड्यूटी पर तैनात हैं, इस आदेश से मुक्त रहेंगे। विशेष अनुमति प्राप्त व्यक्तियों को भी छूट प्रदान की गई है। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस अधिकारीयों ने बताया कि यह कदम किसी भी अप्रिय घटना को रोकने और चुनाव के दौरान सभी मतदान केंद्रों और सार्वजनिक स्थानों को सुरक्षित रखने के लिए उठाया गया है। चुनाव के दौरान हथियारों की अनियंत्रित स्थिति से हिंसा, धमकी और अवैध गतिविधियों की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए पुलिस कमिश्नरेट ने यह आदेश जारी किया है ताकि नागरिकों, मतदान केंद्रों और चुनाव कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

सुरक्षा उपायों के अंतर्गत पुलिस थानों को निर्देशित किया गया है कि वे सभी लाइसेंसधारकों की सूची तैयार करें और हथियार जमा करने की प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता बनाए रखें। इसके अलावा, पुलिस टीमों को अपने-अपने क्षेत्रों में मोबाइल पेट्रोलिंग और संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी भी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां आदर्श आचार संहिता लागू है और चुनाव की गतिविधियां तीव्र होंगी, वहां अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा।

पुलिस कमिश्नर ने कहा कि आदेश का उद्देश्य किसी भी प्रकार की हिंसा या अपराध की संभावना को समाप्त करना है और इसे पूरी तरह निष्पक्ष, सुरक्षित और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के लिए लागू किया गया है। उन्होंने जनता से अपील की है कि वे आदेश का पालन करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें।

विशेषज्ञों के अनुसार, चुनावी सुरक्षा के लिए हथियार जमा करने का यह कदम व्यापक रूप से प्रभावशाली माना जा रहा है। इससे न केवल कानून-व्यवस्था बनाए रखने में मदद मिलेगी, बल्कि मतदान प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की हिंसा या भय फैलाने की कोशिशों को भी रोका जा सकेगा। पुलिस का यह आदेश यह सुनिश्चित करता है कि सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को समान और निष्पक्ष वातावरण में अपनी गतिविधियों को अंजाम देने का अवसर मिले।

मुंबई सेंट्रल में ट्रैक कार्य के कारण ट्रेनों का शॉर्ट टर्मिनेशन

मुंबई सेंट्रल स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 05 पर पूर्ण ट्रैक नवीनीकरण (CTR) कार्य के मद्देनज़र 60 दिनों का ब्लॉक तत्काल प्रभाव से लिया जा रहा है। इसके कारण पश्चिम रेलवे की कुछ ट्रेनें प्रभावित होंगी। प्रभावित ट्रेनों का विवरण निम्नानुसार है :

1. ट्रेन संख्या 22946 ओखा–मुंबई सेंट्रल सौराष्ट्र मेल को तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक दादर स्टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेट किया जाएगा।
2. 07 अप्रैल, 2026 से यात्रा प्रारंभ करने वाली ट्रेन संख्या 22210 हजरत निजामुद्दीन–मुंबई सेंट्रल एक्सप्रेस को अगले आदेश तक प्रत्येक बुधवार एवं रविवार को दादर स्टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेट किया जाएगा।
3. 06 अप्रैल, 2026 से यात्रा प्रारंभ करने वाली ट्रेन संख्या 09186 कानपुर अनवरगंज–मुंबई सेंट्रल एक्सप्रेस को अगले आदेश तक प्रत्येक मंगलवार को दादर स्टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेट किया जाएगा।
4. 09 अप्रैल, 2026 से यात्रा प्रारंभ करने वाली ट्रेन संख्या 09076 काठगोदाम–मुंबई सेंट्रल एक्सप्रेस को अगले आदेश तक प्रत्येक शुक्रवार को दादर स्टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेट किया जाएगा।

पश्चिम रेलवे द्वारा टिकट चेकिंग में नया कीर्तिमान,वित्त वर्ष 2025–26 में प्राप्त किया 209.30 करोड़ का जुर्माना

पश्चिम रेलवे राजस्व संरक्षण सुनिश्चित करने तथा यात्रियों में अनुशासन बढ़ाने के क्षेत्र में निरंतर उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। वरिष्ठ वाणिज्य अधिकारियों के सक्रिय मार्गदर्शन में टिकट चेकिंग स्टाफ की अत्यंत प्रेरित टीम द्वारा मुंबई उपनगरीय लोकल ट्रेनों, लंबी दूरी की मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों, यात्री सेवाओं तथा हॉलिडे स्पेशल ट्रेनों में सघन टिकट चेकिंग अभियान चलाया गया। इसका उद्देश्य राजस्व ह्रास को कम करना तथा यात्रा अनुशासन को सुदृढ़ करना रहा है। पश्चिम रेलवे द्वारा वित्त वर्ष 2025–26 में एक उल्लेखनीय उपलब्धि के रूप में बिना बुक किए गए सामान के मामलों सहित बिना टिकट एवं अनियमित यात्रा के कुल 32.74 लाख मामलों का पता लगाया गया। टिकट जांच अभियानों के माध्यम से रिकॉर्ड 209.30 करोड़ का जुर्माना प्राप्त किया गया, जो लगभग 39% की वृद्धि दर्शाता है। उल्लेखनीय है कि रेलवे बोर्ड द्वारा निर्धारित लक्ष्य 11 महीनों में ही प्राप्त कर लिया गया था।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इस गति को बनाए रखते हुए मार्च 2026 माह में ही 2.87 लाख मामलों का पता लगाया गया, जिससे 18.25 करोड़ का जुर्माना प्राप्त किया गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 10% से अधिक की वृद्धि दर्शाता है। यह निरंतर प्रदर्शन पश्चिम रेलवे की वैध यात्रियों के हितों की रक्षा करने तथा बिना टिकट यात्रा पर अंकुश लगाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

मुंबई उपनगरीय खंड में वित्त वर्ष 2025–26 के दौरान बिना टिकट एवं अनियमित यात्रा के 11.60 लाख से अधिक मामलों का पता लगाया गया, जिससे 54.55 करोड़ का जुर्माना प्राप्त किया गया। मार्च माह में ही एक लाख मामलों का पता लगाया गया, जिससे 4.67 करोड़ प्राप्त की गई।

श्री विनीत ने आगे बताया कि एसी लोकल ट्रेनों में सामान्य टिकट धारकों के अनधिकृत प्रवेश को रोकने के लिए नियमित रूप से औचक टिकट जांच अभियान चलाए जा रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप अप्रैल 2025 से मार्च 2026 की अवधि में ऐसे लगभग 1.3 लाख मामलों का पता लगाया गया तथा 4.18 करोड़ का जुर्माना प्राप्त किया गया, जो पिछले वर्ष के 2.10 करोड़ की तुलना में 99% से अधिक है। पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों से अपील की गई है कि उचित टिकट के साथ यात्रा करें, अनियमित यात्रा से बचें तथा नियमों का पालन कर रेल प्रशासन का सहयोग करें।

इन रिकॉर्ड उपलब्धियों के साथ पश्चिम रेलवे भारतीय रेल में टिकट जांच के क्षेत्र में नए मानक स्थापित करती जा रही है, जो राजस्व संरक्षण एवं यात्री अनुशासन के प्रति उसकी मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है। निरंतर प्रयासों के माध्यम से परिचालन दक्षता बढ़ाने तथा वैध यात्रियों के लिए बेहतर एवं आरामदायक यात्रा वातावरण सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

जेतलसर जंक्शन रेलवे स्टेशन 'अमृत भारत स्टेशन योजना' में शामिल

भारतीय रेल के आधुनिकीकरण एवं यात्री सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में रेलवे बोर्ड द्वारा पश्चिम रेलवे के भावनगर मंडल अंतर्गत जेतलसर जंक्शन रेलवे स्टेशन को 'अमृत भारत स्टेशन योजना' में शामिल करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

भावनगर मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी ने जानकारी देते हुए बताया कि जेतलसर जंक्शन स्टेशन के समग्र विकास हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। इस उन्नयन से न केवल स्टेशन की आधारभूत संरचना में सुधार होगा, बल्कि यात्रियों को आधुनिक एवं उन्नत सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी।

मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा के मार्गदर्शन में 'अमृत भारत स्टेशन योजना' के अंतर्गत जेतलसर जंक्शन का पुनर्विकास आधुनिक मानकों के अनुरूप किया जाएगा। प्रस्तावित कार्यों में उन्नत यात्री प्रतीक्षालय, स्वच्छता सुविधाएं, पार्किंग एरिया का विस्तार,स्टेशन भवन के अग्रभाग का सौंदर्यीकरण, नए कवरशेड, दिव्यांगजन अनुकूल आधुनिक शौचालय ब्लॉक, पेयजल बूथ एवं वाटर कूलर की व्यवस्था, आधुनिक प्लेटफॉर्म, सुगम आवागमन व्यवस्था, डिजिटल सूचना प्रणाली, दिव्यांगजन अनुकूल सुविधाएं, पर्याप्त एवं उन्नत प्रकाश व्यवस्था तथा स्टेशन परिसर का सौंदर्यीकरण शामिल है।

उल्लेखनीय है कि भावनगर मंडल में 'अमृत भारत स्टेशन योजना' के अंतर्गत पूर्व में लगभग 119 करोड़ की लागत से 17 स्टेशनों पर विकास कार्य प्रगति पर है, जो लगभग पूर्णता की ओर है। अब जेतलसर जंक्शन के शामिल होने से इस योजना के अंतर्गत विकसित होने वाले स्टेशनों की संख्या बढ़कर 18 हो गई है। जेतलसर स्टेशन के पुनर्विकास हेतु 16.32 करोड़ की लागत स्वीकृत की गई है, जिससे योजना की कुल लागत बढ़कर 135.32 करोड़ हो गई है।

इस पहल से यात्रियों को सुरक्षित, सुगम एवं आरामदायक यात्रा अनुभव प्राप्त होगा तथा क्षेत्र के सामाजिक एवं आर्थिक विकास को भी नई गति मिलेगी। भारतीय रेल द्वारा देशभर के प्रमुख स्टेशनों को आधुनिक स्वरूप प्रदान करने की दिशा में 'अमृत भारत स्टेशन योजना' एक महत्वपूर्ण एवं दूरदर्शी पहल है, जिसमें जेतलसर जंक्शन का चयन क्षेत्र के लिए गर्व का विषय है।

सूरत रेलवे स्टेशन पर हाईटेक वॉटर मॉनिटरिंग सिस्टम, 24 घंटे नजर रखेगी सुरक्षा

सूरत। यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पश्चिम रेलवे ने सूरत रेलवे स्टेशन पर पानी भरने की प्रक्रिया की निगरानी के लिए पहली बार तकनीक का सहारा लिया है। अब स्टेशन पर "वॉटर वॉच स्मार्ट मॉनिटरिंग सिस्टम" लागू किया गया है, जिसके तहत अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर 15 हाई-रिजॉल्यूशन CCTV कैमरे लगाए गए हैं। इन कैमरों के जरिए ट्रेनों के कोचों में पानी भरने की पूरी प्रक्रिया 24 घंटे लगातार निगरानी में रहेगी।

रेलवे अधिकारियों के अनुसार, ये कैमरे हाई-रिजॉल्यूशन और नाइट विजन तकनीक से लैस हैं, जिससे दिन और रात दोनों समय स्पष्ट निगरानी संभव होगी। कैमरों को इस तरह एंगल किया गया है कि पाइपलाइन, वाटर फिलिंग प्वाइंट और ट्रेन के कोच एक साथ फ्रेम में दिखाई दें। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि ट्रेन के कोचों में पानी भरने की प्रक्रिया में कहीं कोई लापरवाही या गड़बड़ी न हो। इससे न केवल यात्रियों की सुविधा बढ़ेगी, बल्कि तकनीकी खामियों और मानव भूल की संभावना भी कम होगी।

पिछले समय में रेलवे को अक्सर यात्रियों से शिकायतें मिलती थीं कि कई कोचों में पर्याप्त पानी नहीं भरा गया या भरते समय प्रक्रिया में लापरवाही बरती गई। अब कंट्रोल रूम में बैठे अधिकारी रियल टाइम में हर गतिविधि पर नजर रख सकते हैं और किसी भी गड़बड़ी की स्थिति में तुरंत कार्रवाई कर सकते हैं।

इस स्मार्ट सिस्टम का एक बड़ा फायदा पानी की बर्बादी रोकना भी है। अगर कहीं पाइपलाइन से लीकेज हो रहा हो या पानी ओवरफ्लो हो रहा हो, तो कैमरे तुरंत इसे कैप्चर कर लेंगे। इससे न सिर्फ पानी की बचत होगी, बल्कि किसी तकनीकी खराबी का पता भी तुरंत चल जाएगा। इसके अलावा, कैमरों के जरिए वाटर पाइपलाइन के आसपास अनधिकृत लोगों की आवाजाही और संदिग्ध गतिविधियों पर भी नजर रखी जाएगी, जिससे सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत होगी।

सूरत रेलवे स्टेशन पहले से ही CCTV निगरानी के लिए जाना जाता है। स्टेशन पर करीब 40 से अधिक हाई-रिजॉल्यूशन सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जो स्टेशन परिसर में होने वाली गैर-कानूनी गतिविधियों और लोगों की संदिग्ध हरकतों पर कड़ी नजर रखते हैं। ये कैमरे प्लेटफॉर्म, टिकट काउंटर और अन्य कई अहम स्थानों पर लगाए गए हैं। अब पानी भरने की प्रक्रिया पर निगरानी जुड़ने से स्टेशन की सुरक्षा और यात्रियों की सुविधा दोनों में सुधार होगा।

रेलवे अधिकारियों का कहना है कि यह पहल केवल पानी भरने की प्रक्रिया को सुरक्षित बनाने के लिए ही नहीं, बल्कि जल संसाधनों की बचत और तकनीकी खामियों की पहचान के लिए भी महत्वपूर्ण है। हाईटेक निगरानी के जरिए स्टेशन प्रशासन जल्द ही किसी भी समस्या का समाधान कर पाएगा और यात्रियों को बेहतर सुविधा सुनिश्चित कर सकेगा।

स्मार्ट मॉनिटरिंग सिस्टम की शुरुआत से ही रेलवे को उम्मीद है कि यात्रियों को पानी की कमी, ओवरफ्लो या लापरवाही जैसी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। साथ ही, यह कदम रेलवे की सुरक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाएगा और अवैध गतिविधियों या संदिग्ध हरकतों पर तत्काल नजर रखने में मदद करेगा।

सूरत रेलवे स्टेशन पर लगाए गए हाई-रिजॉल्यूशन कैमरे न केवल प्लेटफॉर्म और वाटर पाइपलाइन पर निगरानी रखेंगे, बल्कि स्टेशन परिसर में होने वाली किसी भी संदिग्ध गतिविधि को भी तुरंत पकड़ेंगे। रेलवे का उद्देश्य है कि तकनीक का इस्तेमाल करके यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, और पानी भरने की प्रक्रिया में किसी भी तरह की गड़बड़ी न होने पाए।

यह पहल रेलवे की डिजिटल और हाईटेक निगरानी प्रणाली का एक अहम हिस्सा है। आने वाले समय में इस तरह के स्मार्ट मॉनिटरिंग सिस्टम को अन्य बड़े रेलवे स्टेशनों पर भी लागू करने की योजना है, ताकि पूरे नेटवर्क में यात्रियों को सुरक्षित और सुविधाजनक सेवा प्रदान की जा सके। स्मार्ट वॉटर मॉनिटरिंग सिस्टम के जरिए ट्रेन के कोचों में पानी भरने की प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी। अधिकारी रियल टाइम में हर गतिविधि पर नजर रख सकते हैं, जिससे यात्रियों को बेहतर सेवा मिलेगी और जल संसाधनों की बचत भी होगी। साथ ही, रेलवे कर्मचारियों पर जिम्मेदारी का बोध बढ़ेगा और किसी भी लापरवाही की संभावना कम हो जाएगी।

इस तकनीक के जरिए न सिर्फ पानी भरने की प्रक्रिया की निगरानी होगी, बल्कि स्टेशन की सुरक्षा और यात्री संतोष भी सुनिश्चित होगा। रेलवे अधिकारियों का मानना है कि यह पहल भविष्य में रेलवे के स्मार्ट और सुरक्षित संचालन का एक महत्वपूर्ण उदाहरण बनेगी।

सोना वायदा में 1367 रुपये और चांदी वायदा में 3000 रुपये का ऊछालः क्रूड ऑयल वायदा 153 रुपये फिसला

मुंबईः देश के अग्रणी कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज एमसीएक्स पर कमोडिटी वायदा, ऑप्शंस और इंडेक्स फ्यूचर्स में 118963.47 करोड़ रुपये का टर्नओवर दर्ज हुआ। कमोडिटी वायदाओं में 25429.55 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ, जबकि कमोडिटी ऑप्शंस में 93532.62 करोड़ रुपये का नॉशनल टर्नओवर हुआ। बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स का अप्रैल वायदा 36072 पॉइंट के स्तर पर कारोबार हो रहा था। कमोडिटी ऑप्शंस में कुल प्रीमियम टर्नओवर 2977.89 करोड़ रुपये का हुआ।

कीमती धातुओं में सोना-चांदी के वायदाओं में 16356.34 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। एमसीएक्स सोना जून वायदा 148847 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 151390 रुपये और नीचे में 148298 रुपये पर पहुंचकर, 149680 रुपये के पिछले बंद के सामने 1367 रुपये या 0.91 फीसदी बढ़कर 151047 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर ट्रेड हो रहा था। गोल्ड-गिनी अप्रैल वायदा 968 रुपये या 0.81 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 120280 रुपये प्रति 8 ग्राम पर आ गया। गोल्ड-पेटल अप्रैल वायदा 136 रुपये या 0.91 फीसदी की तेजी के संग 15071 रुपये प्रति 1 ग्राम हुआ। सोना-मिनी मई वायदा 147848 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 149900 रुपये और नीचे में 146682 रुपये पर पहुंचकर, 1470 रुपये या 0.99 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 149610 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। गोल्ड-टेन अप्रैल वायदा प्रति 10 ग्राम सत्र के आरंभ में 147797 रुपये के भाव पर खूलकर, 150290 रुपये के दिन के उच्च और 147137 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 148539 रुपये के पिछले बंद के सामने 1385 रुपये या 0.93 फीसदी की तेजी के संग 149924 रुपये प्रति 10 ग्राम हुआ। चांदी के वायदाओं में चांदी मई वायदा 230716 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 236390 रुपये और नीचे में 229651 रुपये पर पहुंचकर, 232495 रुपये के पिछले बंद के सामने 3000 रुपये या 1.29 फीसदी बढ़कर 235495 रुपये प्रति किलो के भाव पर ट्रेड हो रहा था। इनके अलावा चांदी-मिनी अप्रैल वायदा 2455 रुपये या 1.04 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 238100 रुपये प्रति किलो पर आ गया। जबकि चांदी-माइक्रो अप्रैल वायदा 2380 रुपये या 1.01 फीसदी बढ़कर 238139 रुपये प्रति किलो के भाव पर ट्रेड हो रहा था।

कमोडिटी वायदाओं में 25429.55 करोड़ रुपये और कमोडिटी ऑप्शंस में 93532.62 करोड़ रुपये का दर्ज हुआ टर्नओवर : सोना-चांदी के वायदाओं में 16356.34 करोड़ रुपये का हुआ कारोबार : बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स फ्यूचर्स 36072 पॉइंट के स्तर पर

मेटल वर्ग में 2098.42 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। तांबा अप्रैल वायदा 15.35 रुपये या 1.33 फीसदी की तेजी के संग 1170.45 रुपये प्रति किलो हुआ। जबकि जस्ता अप्रैल वायदा 1.3 रुपये या 0.4 फीसदी की तेजी के संग 324.5 रुपये प्रति किलो के भाव पर पहुंचा। इसके सामने एल्यूमीनियम अप्रैल वायदा 1.75 रुपये या 0.49 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 356.1 रुपये प्रति किलो पर आ गया। जबकि सीसा अप्रैल वायदा 90 पैसे या 0.46 फीसदी चढ़कर 196.15 रुपये प्रति किलो हुआ।

इन जिंसों के अलावा कारोबारियों ने एनर्जी सेगमेंट में 6814.87 करोड़ रुपये के सौदे किए। एमसीएक्स क्रूड ऑयल अप्रैल वायदा सत्र के आरंभ में 10350 रुपये के भाव पर खूलकर, 10510 रुपये के दिन के उच्च और 10162 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 153 रुपये या 1.47 फीसदी गिरकर 10255 रुपये प्रति बैरल हुआ। जबकि क्रूड ऑयल-मिनी अप्रैल वायदा 152 रुपये या 1.46 फीसदी की गिरावट के साथ 10251 रुपये प्रति बैरल के भाव पर कारोबार कर रहा था। इनके अलावा नैचुरल गैस अप्रैल वायदा 268.1 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 269.5 रुपये और नीचे में 261 रुपये पर पहुंचकर, 264 रुपये के पिछले बंद के सामने 2.8 रुपये या 1.06 फीसदी बढ़कर 266.8 रुपये प्रति एमएमबीटीयू के भाव पर ट्रेड हो रहा था। जबकि नैचुरल गैस-मिनी अप्रैल वायदा 2.8 रुपये या 1.06 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 266.8 रुपये प्रति एमएमबीटीयू पर आ गया।

कृषि जिंसों में मेंथा ऑयल अप्रैल वायदा सत्र के आरंभ में 1050 रुपये के भाव पर खूलकर, 3.7 रुपये या 0.35 फीसदी की गिरावट के साथ 1047.1 रुपये प्रति किलो के भाव पर कारोबार कर रहा था।

कारोबार की दृष्टि से एमसीएक्स पर सोना के विभिन्न अनुबंधों में 11580.23 करोड़ रुपये और चांदी के विभिन्न अनुबंधों में 4776.11 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। इसके अलावा तांबा के वायदाओं में 1605.93 करोड़ रुपये, एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम-मिनी के वायदाओं में 302.14 करोड़ रुपये, सीसा और सीसा-मिनी के वायदाओं में 10.07 करोड़ रुपये, जस्ता और जस्ता-मिनी के वायदाओं में 176.11 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

इन जिंसों के अलावा क्रूड ऑयल और क्रूड ऑयल-मिनी के वायदाओं में 5276.09 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। जबकि नैचुरल गैस और नैचुरल गैस-मिनी के वायदाओं में 1503.11 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। मेंथा ऑयल के वायदा में 14.50 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। जबकि कॉटन केंडी के वायदाओं में 0.42 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

ओपन इंटरेस्ट सोना के वायदाओं में 8005 लोट, सोना-मिनी के वायदाओं में 46799 लोट, गोल्ड-गिनी के वायदाओं में 26593 लोट, गोल्ड-पेटल के वायदाओं में 374424 लोट और गोल्ड-टेन के वायदाओं में 52697 लोट के स्तर पर था। जबकि चांदी के वायदाओं में 7090 लोट, चांदी-मिनी के वायदाओं में 19391 लोट और चांदी-माइक्रो वायदाओं में 75323 लोट के स्तर पर था। क्रूड ऑयल के वायदाओं में 23353 लोट और नैचुरल गैस के वायदाओं में 38005 लोट के स्तर पर था।

इंडेक्स फ्यूचर्स में बुलडेक्स अप्रैल वायदा 36002 पॉइंट पर खूलकर, 36101 के उच्च और 36000 के नीचले स्तर को छूकर, 247 पॉइंट बढ़कर 36072 पॉइंट के स्तर पर कारोबार हो रहा था।

कमोडिटी ऑप्शंस ऑन फ्यूचर्स में क्रूड ऑयल अप्रैल 13500 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति बैरल 48.7 रुपये की गिरावट के साथ 152.1 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस अप्रैल 270 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 1.35 रुपये की बढ़त के साथ 13.8 रुपये हुआ।

सोना अप्रैल 170000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 88 रुपये की बढ़त के साथ 598.5 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी अप्रैल 300000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 10 रुपये की गिरावट के साथ 964 रुपये हुआ। तांबा अप्रैल 1200 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 3.68 रुपये की बढ़त के साथ 18.11 रुपये हुआ। जस्ता अप्रैल 330 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 15 पैसे की नरमी के साथ 4.84 रुपये हुआ।

पुट ऑप्शंस में क्रूड ऑयल अप्रैल 9000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति बैरल 15 रुपये की बढ़त के साथ 368.7 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस अप्रैल 270 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 1.6 रुपये की गिरावट के साथ 16.75 रुपये हुआ।

सोना अप्रैल 120000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 22.5 रुपये की बढ़त के साथ 330 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी अप्रैल 150000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 19.5 रुपये की गिरावट के साथ 458.5 रुपये हुआ। तांबा अप्रैल 1150 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 7.36 रुपये की गिरावट के साथ 20.81 रुपये हुआ।

सूरत के नगर निगम चुनाव: कांग्रेस का मेनिफेस्टो जारी रोजगार, टैक्स राहत और सामाजिक न्याय पर विशेष जोर

सूरत। आगामी नगर निगम चुनाव 2026 को लेकर सूरत में राजनीतिक गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं और इसी बीच गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने शहर के लिए अपना नया मेनिफेस्टो जारी कर दिया है। इस मेनिफेस्टो को तैयार करने में पार्टी ने 'कांग्रेस आपके द्वार' और 'जनमंच' जैसे अभियान के जरिए सीधे जनता से सुझाव लिए हैं, ताकि शहर के हर वर्ग की जरूरतों और अपेक्षाओं का वास्तविक प्रतिबिंब दस्तावेज़ में समाहित हो सके। पार्टी नेतृत्व का कहना है कि यह मेनिफेस्टो केवल एक राजनीतिक घोषणा पत्र नहीं बल्कि सूरत के नागरिकों की समस्याओं और उनकी उम्मीदों पर आधारित एक व्यापक विजन डॉक्यूमेंट है, जिसमें रोजगार, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य, शिक्षा, ट्रैफिक, पर्यावरण और बुनियादी सुविधाओं जैसे अहम मुद्दों को प्राथमिकता दी गई है।

पार्टी कार्यकर्ताओं ने पिछले कुछ महीनों में शहर के प्रत्येक वार्ड में जाकर घर-घर संपर्क साधा और लोगों से शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात व्यवस्था, जलापूर्ति, बुनियादी ढांचा और रोजगार जैसी जरूरतों के बारे में फीडबैक लिया। इन सुझावों और आंकड़ों के आधार पर मेनिफेस्टो तैयार किया गया है। कांग्रेस ने मेनिफेस्टो में सबसे बड़े फोकस के रूप में रोजगार और महिला सशक्तिकरण को रखा है। पार्टी ने घोषणा की है कि नगर निगम में 10,000 से अधिक स्थायी नौकरियां दी जाएंगी और वर्तमान में मौजूद आउटसोर्सिंग सिस्टम को पूरी तरह समाप्त किया जाएगा।

महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए पार्टी ने रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी पर 50 प्रतिशत टैक्स में छूट देने का वादा किया है। इसके साथ ही महिलाओं के लिए हर वार्ड में क्रेच सुविधा, वाहनों पर विशेष रियायत और सुरक्षित परिवहन के उपाय किए जाएंगे। बुजुर्ग नागरिकों के लिए मुफ्त

स्वास्थ्य जांच, डायबिटीज और बीपी जैसी बीमारियों की दवाओं की आपूर्ति, हर ज़ोन में मल्टी-स्पेशियलिटी अस्पताल और 24 घंटे हेल्थ सेंटर की सुविधा देने का भी ऐलान किया गया है।

युवाओं के लिए डिजिटल लाइब्रेरी, स्टडी सेंटर और रोजगार के नए अवसरों पर विशेष जोर दिया गया है, ताकि उन्हें शहर में करियर और शिक्षा के बेहतर विकल्प मिल सकें। पर्यावरण संरक्षण और शहर को स्वच्छ बनाने के लिए पार्टी ने तापी नदी के शुद्धिकरण के लिए अलग बजट सुनिश्चित करने, शहर में हर साल 10 प्रतिशत ग्रीन कवर बढ़ाने और 24 घंटे साफ पेयजल उपलब्ध कराने की योजना बनाई है। इसके साथ ही बेहतर ड्रेनेज सिस्टम और बाढ़ की समस्या के स्थायी समाधान पर भी जोर दिया गया है।

शहर के ट्रैफिक और इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार के लिए गड्ढामुक्त सड़कों, नए फ्लाईओवर, मल्टी-लेवल पार्किंग और इलेक्ट्रिक बसों के जरिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट मजबूत करने की योजना बनाई गई है। इसके अलावा समाज कल्याण के तहत 'फेस्टिवल पार्क' बनाने, आधुनिक एनिमल हॉस्पिटल स्थापित करने और फेरीवालों के लिए सुरक्षित वेंडिंग ज़ोन विकसित करने का भी वादा किया गया है। सूरत को 'साइबर फ्री सिटी' बनाने के लिए विशेष कदम उठाने की बात भी मेनिफेस्टो में शामिल की गई है, ताकि शहर में डिजिटल और तकनीकी शिक्षा के अवसर बढ़ सकें और साइबर सुरक्षा के उपाय लागू किए जा सकें।

पार्टी नेताओं ने स्पष्ट किया है कि यह मेनिफेस्टो जनता की भागीदारी से तैयार किया गया है और इसमें सामाजिक न्याय को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। कांग्रेस ने दावा किया है कि यदि जनता उन्हें मौका देती है, तो वे सूरत के विकास और नागरिक सुविधाओं में व्यापक और स्थायी बदलाव लाएंगे। रोजगार, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, ट्रैफिक सुधार, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सामाजिक कल्याण जैसे मुद्दों पर केंद्रित यह मेनिफेस्टो नगर निगम चुनाव में नागरिकों को एक स्पष्ट और ठोस विकल्प प्रदान करता है।

सूरत के नागरिकों के लिए यह मेनिफेस्टो न केवल उनकी दैनिक समस्याओं का समाधान पेश करता है, बल्कि शहर को आधुनिक, सुरक्षित, स्वच्छ और प्रगतिशील बनाने के लिए स्पष्ट रोडमैप भी देता है। कांग्रेस ने यह आश्वासन दिया है कि हर योजना का समयबद्ध क्रियान्वयन किया जाएगा और इसका प्रभाव शहर के हर नागरिक तक पहुंचेगा। पार्टी का यह दावा है कि उनकी नीतियां शहर के आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय विकास को संतुलित और स्थायी रूप से आगे बढ़ाने में मदद करेंगी।

सूरत : सचिन इंडस्ट्रियल एरिया में PNG कनेक्शन के फैसले से उद्योग जगत को मिली राहत, उत्पादन और रोजगार पर पड़ेगा सकारात्मक असर

सूरत। शहर के प्रमुख औद्योगिक केंद्र सचिन इंडस्ट्रियल एरिया में गैस सप्लाई और PNG कनेक्शन को लेकर हाल ही में हुई बैठक ने उद्योग जगत में राहत की सांस दिलाई है। इस बैठक का आयोजन 6 अप्रैल को सचिन नोटिफाइड एरिया अथॉरिटी के कार्यालय में किया गया, जिसमें गुजरात गैस कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी और क्षेत्र के कई उद्योगपति शामिल हुए। बैठक का मकसद उन औद्योगिक इकाइयों की समस्याओं का समाधान करना था, जिनके पास पीएनजी कनेक्शन नहीं होने के कारण उत्पादन प्रभावित हो रहा था और कर्मचारियों के पलायन का खतरा पैदा हो गया था।

हाल के वैश्विक हालात और गैस सप्लाई में आई रुकावट के चलते शहर के औद्योगिक और घरेलू दोनों क्षेत्रों में गैस सिलेंडरों की कमी सामने आई थी। खासकर उन इकाइयों में, जो पीएनजी कनेक्शन के बिना संचालन कर रही थीं, उत्पादन में बाधाएं उत्पन्न हो रही थीं और उनके लिए नियमित कामकाज बनाए रखना मुश्किल हो गया था। इसके चलते कई उद्योगपतियों ने समय पर गुजरात गैस लिमिटेड में आवेदन

किया था, लेकिन लंबित प्रक्रियाओं और प्रशासनिक देरी के कारण समाधान नहीं मिल पा रहा था। इस समस्या को देखते हुए नोटिफाइड चेयरमैन नीलेश गामी ने बैठक बुलाई और उद्योगपतियों के साथ मिलकर तत्काल समाधान निकालने का निर्देश दिया।

बैठक में गुजरात गैस के डिप्टी मैनेजर और उनकी टीम ने PNG कनेक्शन की प्रक्रिया पर विस्तृत प्रेजेंटेशन दिया। उद्योगपतियों को उनके आवेदन और फाइलों के साथ उपस्थित रखा गया, ताकि हर आवेदन पर मौके पर चर्चा हो सके और लंबित मामलों को शीघ्रता से निपटाया जा सके। सेक्रेटरी मयूर गोलवाला की पहल पर कई दिनों से लंबित PNG कनेक्शन के आवेदन तत्काल क्लियर किए गए, जिससे उद्योगपतियों के लिए गैस सप्लाई सुनिश्चित करना आसान हो गया। बैठक में राजेशभाई गोल, भरतभाई त्रापसिया, अमरभाई, अल्पेशभाई रामकृपा, विमल लिम्बासिया, हार्दिक कटारिया और डायरेक्टर भीखाभाई नकरानी सहित कई अन्य उद्योगपति उपस्थित रहे और उन्होंने प्रशासन के सहयोग की सराहना की।

इस पहल को उद्योग जगत के लिए महत्वपूर्ण और राहत भरा कदम माना जा रहा है। इससे न केवल उत्पादन बनाए रखने में मदद मिलेगी, बल्कि कर्मचारियों के पलायन की समस्या पर भी काबू पाया जा सकेगा। उद्योगपतियों का मानना है कि नियमित और भरोसेमंद गैस सप्लाई से उनकी इकाइयों का संचालन स्थिर रहेगा, जिससे रोजगार सुरक्षित रहेंगे और उत्पादन की गुणवत्ता पर भी सकारात्मक असर पड़ेगा।

सचिन इंडस्ट्रियल एरिया में लंबे समय से चली आ रही पीएनजी कनेक्शन की समस्याओं के समाधान के बाद उद्योगपतियों ने प्रशासन और गुजरात गैस कंपनी की तत्परता की सराहना की है। इस कदम से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है और नए उद्योगों के लिए यहां निवेश करने की संभावनाएं भी मजबूत हुई हैं। बैठक में किए गए निर्णय से यह भी साफ हुआ कि उद्योग क्षेत्र की समस्याओं का त्वरित समाधान करने के लिए प्रशासन और कंपनियों के बीच संवाद और सहयोग कितना महत्वपूर्ण है। औद्योगिक क्षेत्र के विशेषज्ञों का कहना है कि PNG कनेक्शन सुनिश्चित होने से उत्पादन में बाधा कम होगी, कर्मचारियों की स्थिरता बनी रहेगी और क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था पर भी सकारात्मक असर पड़ेगा, क्योंकि उत्पादन और रोजगार में स्थिरता से पूरे शहर में व्यापार और सेवा क्षेत्र में भी सुधार आएगा। उद्योगपतियों और प्रशासन के बीच यह सहयोग मॉडल भविष्य में अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में भी लागू किया जा सकता है।

बैठक में लिए गए फैसले के अनुसार, अब सभी लंबित PNG कनेक्शन के आवेदन जल्द से जल्द प्रोसेस किए जाएंगे और नए उद्योगपतियों के लिए भी कनेक्शन की प्रक्रिया आसान बनाई जाएगी। इस पहल के परिणामस्वरूप सचिन इंडस्ट्रियल एरिया में उत्पादन, रोजगार और निवेश के अवसरों में सुधार आने की उम्मीद जताई जा रही है। उद्योगपतियों का मानना है कि यह पहल शहर के औद्योगिक विकास और आर्थिक स्थिरता को मजबूती प्रदान करेगी, जिससे सूरत को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय निवेशकों के लिए और भी आकर्षक औद्योगिक केंद्र बनाया जा सकेगा।

यस बैंक के नए एमडी और सीईओ विनय मुरलीधर टोंसे ने संभाली कमान, बैंकिंग क्षेत्र में तीन दशक से अधिक अनुभव के साथ करेंगे नेतृत्व

नई दिल्ली। भारत के वित्तीय परिदृश्य में महत्वपूर्ण बदलाव की दिशा में एक नया अध्याय शुरू हो गया है, क्योंकि विनय मुरलीधर टोंसे ने यस बैंक के प्रबंध निदेशक (एमडी) और मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) का पदभार ग्रहण कर लिया है। टोंसे ने अपने पूर्ववर्ती प्रशांत कुमार की जगह ली है, जिनका विस्तारित कार्यकाल पांच अप्रैल को समाप्त हुआ। बैंकिंग जगत में टोंसे की नियुक्ति को विशेषज्ञों ने इसे बैंक के विकास और रणनीतिक विस्तार के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया है।

आधिकारिक तौर पर तीन साल के लिए नियुक्त किए गए टोंसे ने छह अप्रैल से ही एमडी एवं सीईओ के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। इस नियुक्ति की प्रक्रिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) की मंजूरी और शेयरधारकों की स्वीकृति के अधीन थी, जो पूरी होने के बाद टोंसे ने पूर्ण अधिकार के साथ बैंक की कमान संभाली।

यस बैंक के बोर्ड ने उनके अनुभव और व्यापक बैंकिंग क्षेत्र में उपलब्ध विशेषज्ञता को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया।

विनय मुरलीधर टोंसे के पास 35 वर्षों से अधिक का समृद्ध अनुभव है। उन्होंने बैंकिंग क्षेत्र में विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे ट्रेजरी, खुदरा बैंकिंग, कॉरपोरेट बैंकिंग, अंतरराष्ट्रीय परिचालन और परिसंपत्ति प्रबंधन में कार्य किया है। इसके अलावा, टोंसे भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) में प्रबंध निदेशक के रूप में भी काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने बड़े पैमाने पर रणनीतिक नीतियों को लागू करने और संगठन के संचालन में सुधार लाने में योगदान दिया। विशेषज्ञों का मानना है कि टोंसे के आने से यस बैंक को अपने विकास के अगले चरण में मजबूती मिलने की संभावना है। उनका अनुभव बैंक की वित्तीय संरचना को मजबूत करने, नवाचार और डिजिटल बैंकिंग सेवाओं के विस्तार के लिए लाभकारी साबित हो सकता है। बैंकिंग क्षेत्र में लगातार बदलती चुनौतियों और प्रतिस्पर्धा के बीच टोंसे के नेतृत्व में यस बैंक ग्राहकों की अपेक्षाओं और शेयरधारकों के हितों को ध्यान में रखते हुए नई योजनाओं और रणनीतियों को लागू करेगा।

यस बैंक के प्रवक्ता ने बताया कि टोंसे की नियुक्ति से बैंक के कर्मचारियों और प्रबंधन में नई ऊर्जा और भरोसा आया है। बैंक की आगामी योजनाओं में नई तकनीकी पहल, डिजिटल उत्पादों का विस्तार, और कॉर्पोरेट तथा खुदरा बैंकिंग क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धात्मक सेवाओं को बढ़ावा देना शामिल है। टोंसे का नेतृत्व बैंक की दीर्घकालिक स्थिरता और वित्तीय स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

टोंसे ने कार्यभार संभालते ही कहा कि उन्हें यस बैंक के कर्मचारियों और ग्राहकों के भरोसे के साथ बैंक का नेतृत्व करने का गर्व है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि उनके नेतृत्व में बैंक नए अवसरों को भुनाएगा, व्यवसाय को स्थिरता और विस्तार की दिशा में ले जाएगा, और सभी हितधारकों के लिए मूल्य निर्माण करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि बैंकिंग क्षेत्र में उनके अनुभव का मुख्य उद्देश्य ग्राहकों को विश्वसनीय, सुरक्षित और नवीन बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना होगा।

विश्लेषकों का यह भी मानना है कि टोंसे की नियुक्ति से यस बैंक की छवि को और मजबूती मिलेगी, क्योंकि उन्होंने पहले विभिन्न संस्थानों में अपनी प्रबंधन क्षमता और रणनीतिक सोच का प्रदर्शन किया है। उनके नेतृत्व में बैंक के लिए नए निवेश, साझेदारी और व्यावसायिक विस्तार के अवसर खुल सकते हैं। इसके अलावा, बैंक के डिजिटल प्लेटफॉर्म को और मजबूत करने और ग्राहकों के अनुभव को बेहतर बनाने पर भी जोर दिया जाएगा।

जयपुर: जयगढ़ किले की पहाड़ियों पर जापानी महिला के साथ बदसलूकी पांच युवकों की हरकत CCTV में कैद, पुलिस ने जांच तेज कर दी

जयपुर। राजस्थान की राजधानी जयपुर, जिसे 'पिंक सिटी' और अपनी मेहमाननवाजी के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है, वहां से एक गंभीर और विचलित करने वाली खबर सामने आई है। रविवार सुबह जापान से आई एक महिला पर्यटक जयगढ़ किले की पहाड़ियों पर घूमने पहुंची, लेकिन उसे पांच युवकों ने घेर लिया और उसके साथ अश्लील हरकतें की। यह घटना न केवल विदेशी पर्यटकों के लिए सुरक्षा की चिंता को बढ़ा रही है, बल्कि शहर की पर्यटन छवि और स्थानीय सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर रही है।

पुलिस के अनुसार महिला सुबह करीब 8:10 बजे जयगढ़ महल देखने जा रही थी। वह महल के पास स्थित गणेश पोल और किले के बीच के रास्ते से गुजर रही थी, तभी पांच युवकों ने उसे अकेला पाकर घेर लिया। आरोपियों ने महिला के साथ अश्लील हरकतें शुरू कर दीं और उसे डराने की कोशिश की। पीड़िता ने तुरंत हिम्मत दिखाई और जोर से चिल्लाना शुरू किया, जिससे पास ही तैनात सुरक्षा गार्ड मौके पर पहुंचे। गार्ड को देखते ही पांचों युवक मौके से भाग खड़े हुए, जो पहाड़ी के नीचे उतरते हुए सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गए।

बदहवास महिला तुरंत जयगढ़ किले के कर्मचारियों के साथ आमेर थाने पहुंची और घटना की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने तुरंत इलाके के CCTV फुटेज खंगाले और आसपास के सभी संदिग्ध व्यक्तियों और स्थानीय बदमाशों की पहचान शुरू

कर दी। जयपुर के SHO गौतम डोटासरा ने बताया कि हुलिए और रिकॉर्ड के आधार पर संभावित आरोपियों की पहचान लगभग पुख्ता हो चुकी है और जल्द ही गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाएगी।

विशेषज्ञों का मानना है कि जयपुर जैसे पर्यटन स्थल, जो अपनी ऐतिहासिक धरोहर और सुरक्षित पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है, वहां इस तरह की घटनाएं विदेशी पर्यटकों में डर और असुरक्षा पैदा करती हैं। नौ दिन पहले ही जलमहल की पाल पर एक विदेशी महिला को घेरा गया था और उसके गले में हाथ डालकर उसे खींचने की कोशिश की गई थी। ऐसे लगातार मामले शहर की पर्यटन छवि को गंभीर नुकसान पहुंचा रहे हैं।

स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने चेतावनी दी है कि ऐसे मामलों को गंभीरता से लिया जाएगा और जयपुर के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। पुलिस ने विशेष टीम गठित कर रखी है, जो सभी संभावित संदिग्धों और घटनास्थलों की निगरानी कर रही है। प्रशासन ने सुरक्षा गार्डों की संख्या बढ़ाने, CCTV कैमरों की कवरेज बढ़ाने और पर्यटकों के मार्गों पर नियमित गश्त करने के निर्देश जारी किए हैं।

स्थानीय पर्यटन व्यवसायियों और होटल मालिकों ने भी इस घटना पर चिंता व्यक्त की है। उनका कहना है कि विदेशी पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना न केवल राज्य की पर्यटन छवि के लिए जरूरी है, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था और व्यापारिक हितों के लिए भी महत्वपूर्ण है। कई होटल और टूर ऑपरेटर अब अपने पर्यटकों के लिए गाइडेड टूर और सुरक्षा उपायों को और कड़ा कर रहे हैं।

इसके अलावा, जयपुर पर्यटन विभाग ने चेतावनी दी है कि विदेशी पर्यटक अकेले पहाड़ी और दूर-दराज़ के स्थलों पर न जाएं। विभाग ने सुझाया है कि पर्यटक हमेशा गाइड के साथ ही किले और अन्य पर्यटन स्थलों की यात्रा करें। पुलिस का कहना है कि आरोपियों की पहचान होते ही उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाएगी और उन्हें सलाखों के पीछे भेजा जाएगा।

यह घटना पूरे राज्य में पर्यटन सुरक्षा पर नई बहस शुरू कर रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि सुरक्षा व्यवस्था में सुधार और सख्त निगरानी के बिना राज्य में विदेशी पर्यटक असहज महसूस करेंगे, जिससे लंबे समय में राजस्थान की पर्यटन प्रतिष्ठा प्रभावित हो सकती है। प्रशासन का उद्देश्य है कि ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति न हो और जयपुर विदेशी पर्यटकों के लिए फिर से सुरक्षित और आकर्षक शहर के रूप में उभरे।

पुलिस और प्रशासन के इस कदम से उम्मीद की जा रही है कि भविष्य में जयपुर के पर्यटन स्थलों पर निगरानी बढ़ेगी और पर्यटकों के साथ किसी भी तरह की अनहोनी से पहले ही रोकथाम की जा सकेगी। साथ ही स्थानीय समुदाय और व्यापारिक प्रतिष्ठान भी प्रशासन के साथ मिलकर सुरक्षा उपायों को और मजबूत करेंगे, ताकि शहर में पर्यटन और सुरक्षा का संतुलन कायम रखा जा सके।

इस पूरे मामले ने यह साफ कर दिया है कि जयपुर जैसी पर्यटन नगरी में सुरक्षा, जागरूकता और तत्पर प्रशासन का होना कितना जरूरी है। राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन इस दिशा में गंभीर हैं और आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पूरे शहर में सुरक्षा कड़ी कर दी जाएगी, ताकि विदेशी और स्थानीय पर्यटक दोनों ही सुरक्षित वातावरण में राजस्थान की संस्कृति और ऐतिहासिक धरोहर का अनुभव कर सकें।

ललिता की जिद और मां का साहस सिस्टम को शर्मसार कर गया: 18 साल के बेटे के कातिल को मां ने ढूंढ निकाला

उत्तराखंड। कभी-कभी इंसान की ममता, जिद और साहस किसी भी सिस्टम की सुस्ती, लापरवाही और गैर-जिम्मेदाराना रवैये को धूल चटा देते हैं। ऐसा ही विचलित करने वाला मामला सामने आया सहस्रधारा रोड निवासी ललिता चौधरी के साथ, जिन्होंने अपने 18 वर्षीय बेटे क्षितिज चौधरी की मौत के पीछे जिम्मेदार कातिल को खुद खोज निकाला। यह तब हुआ जब पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए और फाइनल रिपोर्ट (FR) लगा कर मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया था।

घटना 16 फरवरी 2024 की है। क्षितिज चौधरी प्रेमनगर क्षेत्र में पैदल जा रहा था, तभी एक अनियंत्रित डंपर ने उसे बेरहमी से कुचल दिया। चालक मौके से फरार हो गया। अगले दिन इलाज के दौरान क्षितिज की जान चली गई और घर का चिराग बुझ गया। लेकिन इस अंधेरे समय में ललिता की मां होने की जिम्मेदारी और न्याय की तलाश ने उसे टूटने नहीं दिया। बेटे की मौत के बाद जब ललिता पुलिस स्टेशन पहुंचीं और मामले की प्रगति जानना चाहा, तो उन्हें पुलिस द्वारा अनसुनी किया गया। रिपोर्ट दर्ज करने में आनाकानी की गई और पुलिस ने कहा कि बिना नंबर वाले वाहन को ढूँढना असंभव है। इसके बजाय उन्होंने फाइल में फाइनल रिपोर्ट लगाकर मामला बंद कर दिया, जिससे मां के अंदर गुस्सा और निराशा बढ़ी।

इस गैर-जिम्मेदाराना रवैये से आहत ललिता ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने दुख, शोक और काम को किनारे रखकर खुद मामले की जांच की कमान संभाली। उन्होंने दुर्घटनास्थल और आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज महीनों तक खंगाली, आसपास के दुकानदारों, स्थानीय लोगों और सुरक्षा कर्मियों से पूछताछ की। इस मेहनत के दौरान उन्होंने 10 संदिग्ध वाहनों की सूची तैयार की और संभावित डंपर और उसके मालिक की पहचान की दिशा में लगातार कदम बढ़ाए। डेढ़ साल की लंबी जद्दोजहद और तपस्या के बाद, ललिता ने न केवल उस अज्ञात डंपर को खोज निकाला, बल्कि उसके मालिक अंकित चौहान का भी पता लगा लिया। इस प्रयास के दौरान उन्होंने स्थानीय प्रशासन, पुलिस थाने और तकनीकी साधनों का सहारा लिया। हर कदम पर उन्हें सिस्टम की सुस्ती का सामना करना पड़ा, लेकिन उनकी मां की ममता और न्याय की जिद ने कभी पीछे नहीं हटने दिया।

शनिवार को ललिता चौधरी पुख्ता सबूत और CCTV फुटेज के साथ एसएसपी कार्यालय पहुंचीं। एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोबाल ने मां की इस अदम्य हिम्मत और साहस को देखकर तुरंत फाइनल रिपोर्ट को दरकिनार कर दिया और मामले की दोबारा जांच के आदेश दिए। उन्होंने आश्वासन दिया कि दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और न्याय सुनिश्चित किया जाएगा।

इस पूरे मामले ने यह साबित कर दिया कि मां की ठान लेने की शक्ति किसी भी जादू की छड़ी से कहीं अधिक प्रभावशाली और सशक्त हो सकती है। सिस्टम की सुस्ती और लापरवाही के बावजूद ललिता की मेहनत और जिद ने इंसाफ दिलाने की राह आसान कर दी। यह न केवल ललिता की हिम्मत का प्रमाण है, बल्कि पूरे समाज के लिए संदेश भी है कि अगर नागरिक सच के लिए ठान लें और सक्रिय भागीदारी दिखाएं, तो कानून-व्यवस्था में सुधार संभव है।

मां के अदम्य साहस ने परिवार को भी सुकून दिया। अब उन्हें उम्मीद है कि क्षितिज की मौत का जिम्मेदार पकड़ में आएगा और न्याय प्रक्रिया पूरी होगी। ललिता की यह कहानी साबित करती है कि अगर इंसान में दृढ़ निश्चय और हिम्मत हो, तो वह किसी भी बाधा को पार कर सकता है। यह सिर्फ एक मां की कहानी नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए चेतावनी और प्रेरणा भी है कि न्याय के लिए लड़ना कभी व्यर्थ नहीं होता।

यह घटना स्थानीय प्रशासन और पुलिस को भी झकझोर कर रख दिया है। अधिकारियों ने माना कि नागरिकों की सक्रिय भूमिका और जागरूकता कानून-व्यवस्था के क्रियान्वयन में निर्णायक साबित हो सकती है। ललिता ने यह भी दिखाया कि तकनीकी साधनों, CCTV फुटेज और धैर्य के सहारे एक आम नागरिक भी बड़े अपराधियों तक पहुंच सकता है और न्याय दिला सकता है।

इस कहानी ने यह संदेश भी दिया है कि अगर मां ठान जाए, तो वह सिस्टम की सुस्ती, सरकारी गैर-जिम्मेदारी और अपराधियों की निडरता को भी मात दे सकती है। ललिता की कोशिश, संघर्ष और अंततः सफलता ने साबित किया कि इंसान की जिद, ममता और साहस किसी भी बाधा से बड़े होते हैं।

बिहार में मौसम का मिजाज बदला, 60 किमी/घंटा की रफ्तार से चलेंगी तेज हवाएं, आंधी, बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट

पटना। बिहार के मौसम में अचानक बदलाव ने राज्यवासियों को सावधान रहने के लिए चेतावनी दी है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटे यानी 7 और 8 अप्रैल के दौरान राज्य के कई हिस्सों में आंधी, तेज बारिश और ओलावृष्टि का प्रभाव देखने को मिलेगा। पश्चिमी विक्षोभ और क्षेत्रीय चक्रवाती गतिविधियों के कारण मौसम में यह बदलाव आया है और विशेषज्ञों ने इसे असामान्य मौसमीय गतिविधियों की शुरुआत बताया है। मौसम विभाग ने पहले ही 8 अप्रैल के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी कर राज्यवासियों को सतर्क किया है।

मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, 8 अप्रैल को राज्य के उत्तर-पूर्व, उत्तर-मध्य और उत्तर-पश्चिमी जिलों में तेज हवाओं की रफ्तार 50 से 60 किमी/घंटा तक रहने का अनुमान है। इसके साथ ही बिजली कड़कने, गरज-चमक के साथ तेज बारिश और ओलावृष्टि की संभावना भी है। ऑरेंज अलर्ट वाले जिलों में अररिया, दरभंगा, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, किशनगंज, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, समस्तीपुर, शिवहर, सीतामढ़ी और सुपौल शामिल हैं। इन जिलों में विशेष रूप से ओलावृष्टि का खतरा अधिक बताया गया है, इसलिए किसानों और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

येलो अलर्ट वाले जिलों में गोपालगंज, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा, सारण, सीवान और वैशाली शामिल हैं। यहां तेज हवाओं और बारिश का असर रहेगा, लेकिन ओलावृष्टि की संभावना अपेक्षाकृत कम है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि 7 अप्रैल को भी राज्य के अधिकांश जिलों में हवाओं की रफ्तार 40–50 किमी/घंटा तक रहेगी और गरज-चमक के साथ बारिश होगी। इस दौरान बिजली गिरने की घटनाओं के चलते लोगों को अतिरिक्त सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है।

तापमान में गिरावट भी मौसम का हिस्सा रहेगी। 8 अप्रैल को अधिकांश जिलों में अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहने का अनुमान है। पटना समेत दक्षिण-मध्य और दक्षिण-पूर्व बिहार में अधिकतम तापमान लगभग 26 डिग्री के आसपास रहेगा, जिससे हल्की ठंडक महसूस की जा सकती है। मौसम विभाग ने चेताया है कि किसानों और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोग अपने फसलों और जानवरों की सुरक्षा के लिए विशेष तैयारी करें।

मौसम विज्ञानियों ने बताया कि 7 और 8 अप्रैल के दौरान तेज हवाओं और बारिश की स्थिति से बाढ़ और पेड़ गिरने जैसी घटनाओं की आशंका भी बढ़ जाएगी। विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां पिछले दिनों भारी बारिश हुई है, वहां नदियों और नालों के किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। इसके अलावा, बिजली गिरने और ओलावृष्टि की घटनाओं से बचाव के लिए सभी को अपने घरों और कार्यालयों में सुरक्षा उपाय अपनाने की आवश्यकता है।

मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि 9 अप्रैल तक राज्य में आंधी-बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। इसके बाद 10 अप्रैल से मौसम में सुधार शुरू होगा और 12 अप्रैल तक तापमान में तेजी से बढ़ोतरी की संभावना है। इस अवधि में अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि मौसम में अचानक बदलाव और ठंडक के कारण लोगों को बीमारियों जैसे सर्दी, खांसी और वायरल फीवर से बचाव के लिए सावधानी बरतनी चाहिए। सरकारी अधिकारियों ने भी चेताया है कि तेज हवाओं और ओलावृष्टि के दौरान बिजली के खंभों, बड़े पेड़ों और कमजोर संरचनाओं के पास नहीं जाना चाहिए। ग्रामीण इलाकों में किसानों को अपने खेतों और फसलों की सुरक्षा के लिए अस्थायी आवरण और संरचना का उपयोग करने की सलाह दी गई है। स्कूलों और कार्यालयों में भी आवश्यकतानुसार छूट और कार्य समय में बदलाव पर विचार किया जा सकता है।

विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि इस मौसमी बदलाव का प्रभाव कृषि, यातायात और सामान्य जीवन पर भी पड़ेगा। किसानों को हल्की और ताजा फसलों की रक्षा के लिए ओले या तेज बारिश से बचाव के उपाय करने चाहिए। साथ ही, शहरों में निर्माण कार्य और सड़क निर्माण में कार्यरत मजदूरों को भी सुरक्षा निर्देशों का पालन करना होगा।

इस बार के मौसम परिवर्तन को देखते हुए लोगों को अपने घरों और वाहनों को सुरक्षित स्थानों पर रखने, बच्चों और बुजुर्गों को बाहर जाने से रोकने और आवश्यक आपातकालीन वस्तुएं तैयार रखने की सलाह दी गई है। इसके अलावा, राज्यभर के स्वास्थ्य केंद्रों को भी तैयार रहने और आपातकालीन परिस्थितियों में सहायता देने के निर्देश दिए गए हैं।

मौसम विभाग ने अंतिम चेतावनी दी है कि तेज हवाओं और ओलावृष्टि के दौरान वाहन चलाने से बचें, छोटे नावों और जलयान का उपयोग न करें और ऊंची इमारतों या खुले मैदानों में अनावश्यक समय न बिताएं। सभी प्रशासनिक विभाग और स्थानीय प्रशासन को भी सतर्क रहने और आवश्यक बचाव उपाय लागू करने के आदेश दिए गए हैं।

इस मौसम बदलाव की गंभीरता को देखते हुए यह स्पष्ट हो गया है कि अगले दो दिनों में बिहारवासियों को विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। तेज हवाओं, बारिश और ओले के साथ आने वाले इन असामान्य मौसमीय प्रभावों से बचने के लिए सभी को सावधानी और पूर्व तैयारी बरतने की सलाह दी गई है।